▪ RNI No. : TNHIN/2013/5252 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 84 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 17-10-2025 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर जीत हासिल करेगा राजग : मोहन यादव

6 संवेदनशीलता से ही रोके जा सकेंगे बाल अपराध

7 प्रेम, बुद्धिमत्ता और नारी शक्ति का उत्सव है : कावेरी कपूर

फर्स्ट टेक

सीरियाई रक्षा मंत्रालय की बस में बम विस्फोट

दमिश्क (सीरिया)/एपी। सीरिया के पूर्वी हिस्से में बृहस्पतिवार को रक्षा मंत्रालय की एक बस में बम विस्फोट हुआ, जिसमें चार सैनिक मारे गए और अन्य घायल हो गए। एक मंत्री ने इसकी जानकारी दी। तेल मंत्री मोहम्मद अल-बशीर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा सैनिक तेल सुविधा में सुरक्षा कर्मियों के रूप में तैनात थे और ड्यूटी पर जाते समय उनकी बस में विस्फोट हुआ। सरकारी अल-इखबरिया टीवी ने बताया कि विस्फोट पूर्वी शहरों देइर अल-ज़ौर और मायादीन को जोड़ने वाली सड़क पर हुआ। खबर में बताया गया है कि सैनिक इराक की सीमा से लगे तेल समृद्ध क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान में तैनात थे। किसी ने भी हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है लेकिन यह इलाका इस्लामिक स्टेट(आईएस) समूह के 'स्लीपर सेल' का गढ़ माना जाता है। आईएस को 2019 में सीरिया में पराजित किया गया था। आईएस, जिसने एक समय पर सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर रखा था।

इजराइली हमले में यमन के हूती विद्रोहियों के सेना प्रमुख की मौत

दुबई/एपी। यमन के हूती विद्रोहियों के नेताओं को निशाना बनाकर अगस्त में किए गए इजराइली हमले में समूह के सेना प्रमुख की मौत हो गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गाजा पट्टी में संघर्षविराम होने के बावजूद हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। हूती विद्रोहियों ने स्वीकार किया है कि इजराइली हमले में मेजर जनरल मुहम्मद अब्दुल करीम अल-गमारी की मौत हो गई है, जिसे देश में एक दशक से जारी युद्ध में उसकी भूमिका के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हूती विद्रोहियों के सेना प्रमुख की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अल-गमारी की मौत हमले में लगी चोटों के कारण हुई। काट्ज ने 28 अगस्त को किए गए हमलों का हवाला देते हुए यह बात कही। तब हुए हमले में हूती विद्रोही समूह के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की भी मौत हो गई थी।

17-10-2025 सूर्यास्त 5:48 बजे | 18-10-2025 सूर्योदय 5:59 बजे

BSE 83,467.66 (+862.23) | NSE 25,585.30 (+261.75)

सोना 12,783 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम | चांदी 177,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

क्या-क्या बाँटोगे

प्रतिबंधित एयरस्पेस हुए,
अवरोध बने सीमाओं पे।
नदियों का जल भी बाँट लिया,
झगड़ा वृक्षों की छाँहों पे।
सागर के पानी पर लकीर,
भूगर्भ युद्ध के दावों पे।
बादल खुशबू अरदास करे,
अंकुश ना लगे हवाओं पे।।

इक्कीसवीं सदी भारत की, 2047 तक 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कुरनूल/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि 21वीं सदी 140 करोड़ भारतीयों की है और 2047 तक 'विकसित भारत' का सपना साकार हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर बिजली क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया।

भारत के 'मेक इन इंडिया' पारिस्थितिकी तंत्र की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा, हमने 'ऑपरेशन सिंदूर' में घरेलू स्तर पर निर्मित 'उपकरणों' की ताकत देखी, जो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया सैन्य अभियान था।

प्रधानमंत्री ने आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपए किए जाने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ढांचे में सुधार जैसे हालिया घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि नागरिक-केंद्रित विकास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के बाद यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि (आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री) चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, 2047 में आजादी के शताब्दी वर्ष तक 'विकसित भारत' का सपना साकार हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी 140 करोड़ भारतीयों की है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को 21वीं सदी के नए विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही है और इस सफलता का आधार 'आत्मनिर्भर भारत' का दृष्टिकोण है, जबकि आंध्र प्रदेश इसकी सफलता का प्रमुख केंद्र बन रहा है।

मोदी ने आरोप लगाया कि 11 साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब प्रति व्यक्ति बिजली की औसत खपत 1,000 यूनिट से भी कम थी, लेकिन उस समय देश को 'ब्लैकआउट' जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और ''हमारे गांवों में बिजली के खंभे तक नहीं थे। उन्होंने कहा, मित्रो, स्वच्छ ऊर्जा से लेकर देश के कुल ऊर्जा उत्पादन तक, भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रहा है।

ट्रंप से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री : राहुल

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए दावे को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ट्रंप से डरे हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, वह (मोदी) मेरे मित्र हैं। हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे मित्र ने मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से कोई तेल खरीद नहीं होगी। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। उन्होंने ट्रंप को यह निर्णय लेने दिया और घोषणा करने दी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी बार-बार आलोचना के बावजूद ट्रंप को सराहना वाले संदेश भेजते रहते हैं।

सभी भगोड़ों को वापस लाने के लिए निश्चित प्रणाली जरूरी : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक अपराधियों, साइबर अपराधियों, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों और अन्य सभी भगोड़ों के प्रति कठोर रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के दायरे में लाया जा सके।

सीबीआई द्वारा यहां आयोजित 'भगोड़ों का प्रत्यर्पण – चुनौतियां और रणनीतियां' विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शाह ने सभी राज्यों से कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की जेल कोठरी स्थापित करने का भी आग्रह किया ताकि विदेशी अदालतों में भगोड़ों द्वारा दी जाने वाली निम्न स्तर की जेल की दलीलों को खारिज किया जा सके। उन्होंने कहा कि न केवल भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध, बल्कि भारत के बाहर से सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध भी कतई बर्दाश्त नहीं करने का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने और इसके लिए एक निश्चित तंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा, चाहे वे आर्थिक अपराधी हों, साइबर अपराधी हों, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हों या संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा हों, प्रत्येक भगोड़े के विरुद्ध कठोर रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के समक्ष लाया जा सके। इसके लिए समय आ गया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इसके लिए अचूक उपाय किए हैं।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुणे/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' को भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि इस मिशन के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए अधिकतर उपकरण स्वदेशी थे। सिंह ने कहा कि भारत ने अब ''उस बाधा को तोड़ दिया है'' जो आजादी के बाद से बनी हुई थी और सरकार ने देश के भीतर हथियारों के निर्माण को जोर शोर से बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक घरेलू रक्षा विनिर्माण को तीन लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना और रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है।

केंद्रीय मंत्री ने पुणे में 'सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी' के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हमने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में यह मुश्किल था क्योंकि हम पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे थे। आजादी के बाद से हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। हमारे लिए विदेशों से रक्षा उपकरण खरीदना एक जरूरत बन गई थी और स्वदेशी उत्पादन लगभग न के बराबर था। मंत्री ने कहा कि भारत ने अब ''उस बाधा को तोड़ दिया है'' जो आजादी के बाद से बनी हुई थी। उन्होंने कहा, हमने देश में ही हथियारों के निर्माण को जोर शोर से बढ़ावा दिया है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि देश रक्षा खरीद के मामले में एक सुविधाजनक स्थिति में पहुंच गया था।

जलवायु और तकनीकी बदलावों के बीच नई मानवाधिकार चुनौतियां सामने आ रहीं : कोविंद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को आगाह किया कि तेजी से हो रहे तकनीकी और पर्यावरणीय बदलाव मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं और खासकर अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों तथा जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन का सामना कर रहे लोगों के लिए अधिक चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, आर्थिक प्रगति हमेशा मानवीय गरिमा के साथ-साथ चलनी चाहिए।

कोविंद ने कहा, जलवायु परिवर्तन अब केवल एक पर्यावरणीय चिंता नहीं रह गया है, बल्कि यह मानवाधिकारों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बनता जा रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 32वें स्थापना दिवस और जेल में बंद कैदियों के मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, कोविंद ने कहा कि भारत की प्रगति को केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी मापा जाना चाहिए कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों की गरिमा और कल्याण को कैसे बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि भारत ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत संवैधानिक और संस्थागत ढांचा तैयार किया है, लेकिन सच्ची प्रगति करुणा और समावेश पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, मानवाधिकार केवल वैधानिक अधिकार नहीं हैं, बल्कि एक गहन नैतिक और सभ्यतागत चेतना की अभिव्यक्ति हैं।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि धर्म, करुणा और न्याय के आदर्शों में निहित भारत की सांस्कृतिक विरासत, मानवीय गरिमा के प्रति उसके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती रहती है।

पिछले तीन दशकों में कमजोर लोगों को आवाज देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रशंसा करते हुए, कोविंद ने कहा कि हिरासत में न्याय, बंधुआ मजदूरी, तस्करी और महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए आयोग के प्रयासों ने ''राष्ट्र की अंतरात्मा पर एक अमिट छाप'' छोड़ी है। जेल सुधारों के विषय पर, उन्होंने कहा, हिरासत में बंद व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा या अमानवीय व्यवहार हमारे संवैधानिक और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है।

ट्रंप का दावा

मोदी ने रूस से तेल नहीं खरीदने का आश्वासन दिया

वाशिंगटन/भाषा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके ''मित्र'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने साथ ही कहा कि यह कदम यूक्रेन पर आक्रमण रोकने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की दिशा में एक ''बड़ा कदम'' होगा। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत द्वारा रूस से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद जारी रखना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसका भारत और अमेरिका के संबंधों पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ा है। ट्रंप ने बुधवार को अपने 'ओवल' कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका इस बात से ''खुश नहीं'' है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी खरीद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध के लिए वित्तपोषण में मदद मिलती है।

रूसी हमलों से यूक्रेन में घना अंधेरा छाया

जेलेंस्की ने ट्रंप से मदद की गुहार लगायी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कीव/एपी। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से हमला किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और अधिक अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली एवं लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं।

यूक्रेन की राष्ट्रीय ऊर्जा संचालक कंपनी, यूक्रेनेर्गो ने बताया कि ड्रोन एवं मिसाइल हमलों के बाद आठ यूक्रेनी क्षेत्रों में बिजली काटनी पड़ी। देश की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी, डीटीईके ने राजधानी कीव में बिजली गुल होने की सूचना दी और कहा कि हमलों के कारण उसे मध्य पोल्टावा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस निष्कर्षण रोकना पड़ा।

जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और 37 मिसाइलें दागीं। उन्होंने रूस पर क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करने और ग्रिड की मरम्मत में लगे आपातकालीन कर्मचारियों एवं इंजीनियरों को निशाना बनाने के लिए एक ही लक्ष्य पर बार-बार हमले करने का आरोप लगाया।

जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा, इस मौसम में, रूसी हर दिन हमारे ऊर्जा ढांचे पर हमला कर रहे हैं। जेलेंस्की के शुक्रवार को ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ बैठक से पहले बृहस्पतिवार को अमेरिका पहुंचने की उम्मीद है।

वफादार कांग्रेसी होने के नाते 2019 में भाजपा के प्रस्ताव के बजाय जेल जाना पसंद किया : शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने 2019 में प्रदेश की कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार को अस्थिर करने तथा नयी सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद देने के विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की पेशकश से इनकार कर दिया था और ऐसे करने के बजाये उन्होंने जेल जाना पसंद किया था। शिवकुमार ने बुधवार को के एम रघु द्वारा लिखित अपनी पुस्तक ए सिंबल ऑफ लॉयल्टी ''डी के शिवकुमार'' के विमोचन के अवसर पर यह बात कही।

भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने दावा किया है कि 'नवंबर क्रांति' से पहले शिवकुमार ने कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को संकेतों में यह संदेश दिया है कि अगर सत्ता का हस्तांतरण कर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उनके पास दूसरा विकल्प भी मौजूद है। राज्य में नवंबर में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के बदले जाने की अटकलें हैं, जिसे कुछ लोग नवंबर क्रांति' कह रहे हैं।

शिवकुमार ने कहा, ''मैं कनकपुरा में था, यहां मेरे दोस्त जानते हैं, मैं दौड़ा आया, क्योंकि दस लोग (विधायक) अपना इस्तीफा सौंपने (2019 में) विधानसभा अध्यक्ष के पास गए थे। मैं पांच से छह विधायकों को वापस लाया। उस समय, मुझे दिल्ली से फोन आया। मैं अभी नहीं बताऊंगा कि भाजपा के उस व्यक्ति का नाम जिसने मुझे आयकर आडिटर के फोन पर कॉल किया था। मेरे भाई (पूर्व सांसद डी के सुरेश) भी मेरे साथ थे।''

सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ''यहां एक डीजी थे, उन्होंने भी बात की, वो दूसरे फोन पर थे। दिल्ली से मुझसे पूछा गया कि आप उप-मुख्यमंत्री बनेंगे या जेल जायेंगे। मुझे इन दो विकल्पों में से एक चुनने और विधायकों को वापस भेजने को कहा गया।'' उन्होंने कहा कि उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। शिवकुमार ने कहा, ''क्या करें। पार्टी के प्रति वफ़ादारी थी, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही (पूर्व प्रधानमंत्री) राजीव गांधी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया, (पूर्व मुख्यमंत्री) एस बंगारप्पा के सहयोग से मुझे मंत्री बनाया। मैं अब तक काफ़ी आगे बढ़ चुका हूं।''

उन्होंने कहा, मैंने (फोन पर भाजपा नेता से) कहा - ''मैं उपमुख्यमंत्री बनने की बजाय जेल जाना पसंद करूंगा। मैं तब (उपमुख्यमंत्री) बन सकता था। पता नहीं राजनीति में क्या होता। लेकिन, मैं अपनी पार्टी, कार्यकर्ताओं, विचारधारा, जिस रास्ते पर मैं आगे बढ़ा, और अपने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के साथ खड़ा रहा।''

हालांकि, जुलाई 2019 में एच. डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जद(एस) की अस्थिर सरकार गिर गई, क्योंकि 17 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर हो गए। इससे भाजपा के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। शिवकुमार को तीन सितंबर, 2019 को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें उसी वर्ष अक्टूबर में जमानत दे दी थी।

शिवकुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, डी.के. शिवकुमार बिना मतलब के कुछ नहीं करते।

वह सिद्दरामय्या और कांग्रेस नेतृत्व को संदेश दे रहे हैं कि अगर उन्हें सत्ता नहीं दी गई तो उनके पास दूसरे विकल्प भी है। वह कांग्रेस के प्रति अपनी वफ़ादारी का भी संदेश दे रहे हैं। भाजपा नेता ने दावा किया, ''वह (शिवकुमार) राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सिद्दरामय्या को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके दावे सच हैं, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्हें किसने, किस समय, किस फ़ोन नंबर से और किसलिए फ़ोन किया था।'' विपक्ष के नेता ने दावा किया, शिवकुमार भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल जा चुके हैं। उनके दावे का इससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर वह अब ऐसा कह रहे हैं, तो वह एक संदेश दे रहे हैं; ''यह कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के लिए एक ख़तरा है।''

भाजपा विधायक ने हिंदू लड़कियों को दी सलाह, जिम न जाएं; 'बड़ी साजिश' का हवाला दिया

मुंबई/भाषा। भाजपा विधायक गोपीचंद पडालकर ने बृहस्पतिवार को एक 'बड़ी साजिश' का हवाला देते हुए यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को जिम जाने के बजाय घर पर ही योग करना चाहिए जहां 'आप नहीं जानते कि जिम में प्रशिक्षक कौन है?''

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए पडालकर ने किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि ''वे'' (स्पष्ट रूप से दूसरे समुदाय के सदस्यों का संदर्भ देते हुए) महिलाओं को लुभा रहे हैं।

पडालकर ने कहा, हिंदू लड़कियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे ऐसे जिम न जाएं जहां उन्हें पता नहीं होता कि ट्रेनर कौन है। बेहतर होगा कि आप घर पर ही योग करें। आपको नहीं पता कि यह कितनी बड़ी साजिश है। हिंदू युवतियों से कहें कि उन्हें घर पर ही योग या व्यायाम करना चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है।

प्रियंक खरगे को धमकी देने वाले व्यक्ति को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु पुलिस ने महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे को फोन किया था और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को पत्र लिखने को लेकर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कीं। इस आरोपी ने जब खरगे को फोन किया था तब मंत्री ने इस बातचीत का वीडियो बना लिया। उसके बाद सदाशिवनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।

'बेंगलूरु सेंट्रल डिवीजन' और कलबुर्गी पुलिस के संयुक्त अभियान में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पहचान धनेश नरोने उर्फ दानप्पा नरोने के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र के सोलापुर का रहने वाला है। सोलापुर कर्नाटक की सीमा से लगा हुआ एक जिला है। खरगे को फोन पर गालियां देने के बाद आरोपी अपने शहर से भागकर लातूर में छिप गया था। लेकिन बेंगलूरु और कलबुर्गी की पुलिस टीम ने उसका पता लगाया, उसे गिरफ्तार किया और बेंगलूरु ले आई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि धनेश बिस्कुट और कन्फेक्शनरी बनाने वाली कंपनियों के लिए मार्केटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है।

उसने एक सर्च इंजन की मदद से खरगे का फ़ोन नंबर हासिल किया था। बेंगलूरु पुलिस धनेश के पिछले रिकॉर्ड और ऐसे अपराधों में उसकी संलिप्तता की जांच के लिए पूछताछ कर रही है। खरगे ने बुधवार को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कथित तौर पर धनेश द्वारा की गई कॉल शामिल है। आरोपी ने मंत्री को उनके उस पत्र के लिए गाली दी जिसमें उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी। मंत्री ने 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति फोन कॉल पर उन्हें गालियां और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा है। सिद्दरामय्या ने कहा कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, जबकि राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। भाजपा ने खरगे के इस रुख की कड़ी आलोचना की और उन्हें राज्य में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती भी दी।

मंत्री ने हाल में सिद्दरामय्या को एक पत्र लिखकर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था।

हेब्बाल में भी हुई है वोटों की चोरी!

- क्षेत्र के विधायक और शहरी विकास मंत्री ने दी विस्फोटक जानकारी
- 20 हज़ार से ज़्यादा वोट चोरी हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहरी विकास मंत्री बैराती सुरेश, जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, ने विस्फोटक जानकारी दी है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों में बेंगलूरु शहर के हेब्बाल निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की चोरी हुई है। मंत्री ने यह गंभीर आरोप गुरुवार को हेब्बाल निर्वाचन क्षेत्र के आर.टी. नगर में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा वोट चोरी के खिलाफ आयोजित हस्ताक्षर संग्रह अभियान में लगाया। पिछले विधानसभा चुनावों में हेब्बाल में 20 हज़ार से ज़्यादा वोट चोरी हुए थे। हालाँकि, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और मतदाताओं ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे 32 हज़ार से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दिलाई। मैं उनका आभारी हूँ।

लोकतंत्र में सभी को एक बार ही वोट देने का अधिकार दिया जाता है। भाजपा उस एक वोट को छीनने की कोशिश करती रही है। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि इसके ज़रिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान हज़ारों लोग आते हैं, जबकि वे हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहते। वे बेंगलूरु के बाहरी इलाके से यहाँ आते हैं और वोट देते हैं। वे अगले चुनावों में फिर आएंगे।उन्होंने आगे कहा कि गंगेनहल्ली वार्ड के एक पते वाले एक हज़ार से ज़्यादा लोग वोट देने आते हैं। यह कैसे संभव है?

उन्होंने कहा कि भाजपा जातियों और धर्मों के बीच नफ़रत के बीज बोकर देश और राज्यों को बाँटने का काम करती रही है। इस पार्टी को मंदिर-मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं सूझ रहा। उस पार्टी का कोई भी नेता देश और राज्य के विकास की बात नहीं करता। इसके बजाय, बैराती सुरेश ने उन पर नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि गरीबों, दलितों और कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाने वाली पार्टी कांग्रेस है। केवल हमारी पार्टी ही देश और राज्य का निर्माण कर सकती है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि हर जगह इस तरह के वोट डाले जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और हेब्बाल निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सावधान रहना चाहिए। मतदाताओं को मामलों की पहचान करने और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना चाहिए। आगामी दिनों में ग्रेटर बेंगलूरु प्राधिकरण के नगर निगमों के चुनाव होने हैं, इसलिए उन्होंने मतदाता सूचियों की पूरी सावधानी से जाँच करने और मतदान को रोकने का आह्वान किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया।

जम्मू-कश्मीर के मुद्दों का समाधान राज्य का दर्जा बहाल करने में निहित है: उमर अब्दुल्ला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में ही जम्मू-कश्मीर के सभी मुद्दों का समाधान निहित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से किए गए राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी अपने वादे को पूरा करने का अनुरोध किया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) सरकार का बृहस्पतिवार को एक वर्ष पूरा होने पर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखने और पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने का संकल्प लिया।

अब्दुल्ला ने कहा, हमें उम्मीद थी कि केंद्र हमारी सरकार के पहले साल में (जम्मू-कश्मीर को) राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मोदी सरकार से संसद और उच्चतम न्यायालय में केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, किसी केंद्र शासित प्रदेश में सरकार का नेतृत्व करना एक अलग अनुभव होता है। हमें उम्मीद थी कि केंद्र राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हम अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटेंगे।

अब्दुल्ला ने यहां नेकां मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, हमारा अब भी मानना है कि जम्मू-कश्मीर के समक्ष सभी समस्याओं का समाधान राज्य का दर्जा बहाल करने में निहित है।

प्रधानमंत्री से राज्य का दर्जा देने संबंधी वादा पूरा करने का आग्रह करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, एक बार फिर, मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम से आग्रह करना चाहूंगा कि वे जम्मू-कश्मीर के लोगों से किया गया वादा पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक वर्ष पहले सरकार की बागडोर संभाली थी और विकास कार्यों में तेजी लाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने शुरुआत कर दी है। चाहे वह जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे पर विधानसभा में प्रस्ताव लाने का जनता से किया गया राजनीतिक वादा हो, या राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित कराना हो - हमने दोनों काम किए। नेकां सरकार का एक साल का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करने की विपक्षी दलों की मांग का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जब उनकी पार्टी ने लोगों से वोट मांगे थे, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार सिर्फ छह महीने या एक साल तक नहीं, बल्कि पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने विधानसभा में कहा था, यदि आपको हमारे घोषणापत्र के आधार पर हमारा मूल्यांकन करना है तो ऐसा सरकार के पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद कीजिए, क्योंकि कोई भी सरकार छह महीने या एक वर्ष में अपने सभी वादे पूरे नहीं करती है। उन्होंने कहा कि नेकां सरकार लोगों से किए गए वादों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वह पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी।

कर्नाटक ने सट्टेबाजी से संबंधित धनशोधन मामले में कांग्रेस विधायक की ईडी गिरफ्तारी पर लगायी मुहर

बेंगलूरु/नई दिल्ली। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सट्टेबाजी से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी द्वारा चित्रदुर्ग के कांग्रेस विधायक के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने वीरेंद्र (50) की पत्नी की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने एजेंसी द्वारा वीरेंद्र को गिरफ्तार किये जाने को अवैध और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का अनुरोध किया था। ईडी ने कांग्रेस विधायक को अगस्त में सिक्किम से गिरफ्तार किया था, जहां वह एक कसीनो किराए पर लेने के लिए व्यावसायिक यात्रा पर गए थे। वीरेंद्र फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

कांग्रेस विधायक की पत्नी आर डी चैत्रा ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में कहा था कि वीरेंद्र के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस प्राथमिकी बंद कर दी गई हैं या उनमें छेड़छाड़ की गयी है और केवल एक शिकायत (संख्या 218/2022) लंबित है। उन्होंने कहा कि यह शिकायत भी 30,000 रुपये के विवाद से संबंधित थी, जिसे दिवानी मामला माना गया है तथा ईडी के अनुसार जांच एजेंसी (पुलिस) द्वारा 'बी' रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दायर की गई।

ईडी ने विधायक पर कई पुलिस प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था, जिनमें अवैध ऑनलाइन/ऑफलाइन सट्टेबाजी और जुए के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। एजेंसी का दावा है कि वीरेंद्र और उनके साथी फोनपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ' जैसे भुगतान मंच का इस्तेमाल कर किंग567' जैसा अवैध सट्टेबाजी मंच चलाते थे।

वीरेंद्र की पत्नी ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय को बताया कि उनके पति के खिलाफ फोनपैसा या सट्टेबाजी से कोई सीधा संबंध या आरोप नहीं हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अधिकार क्षेत्र से बाहर है और पीएमएलए की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है।

ईडी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पीएमएलए (धन शोधन रोकथाम अधिनियम) के तहत पूर्व शर्त को पूरा करने वाले अपराध का अस्तित्व है, क्योंकि धन शोधन निरोधक कानून के तहत कार्यवाही तब तक जारी रह सकती है जब तक कि 'बी' रिपोर्ट न्यायिक रूप से स्वीकार नहीं कर ली जाती। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के पास 'पर्याप्त' सामग्री मौजूद है, जो यह मानने के लिए पर्याप्त कारण देती है कि याचिकाकर्ता का पति पीएमएलए, 2002 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि तदनुसार, उक्त रिट याचिका खारिज की जाती है तथा जमानत याचिका दायर करने की छूट दी जाती है।

सर्वेक्षण

बेंगलूरु में गुरुवार को आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के लिए कावेरी स्थित अपने आवास पर पहुंचे कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या।

नियुक्ति

बेंगलूरु में गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल थावरचन्द गहलोत ने डॉ. रिचर्ड विंसेंट डिसूजा, बी. वेंकट सिंह और डॉ. महेश वाल्वेकर को पद की शपथ दिलाई, जिन्हें कर्नाटक राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नव नियुक्त किया गया है।

दिवाली से पहले सोने में उछाल; आभूषण के बजाय छड़, सिक्के खरीद रहे हैं ग्राहक

मुंबई/भाषा। व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिवाली और शादी के मौसम से पहले सोने की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर हैं, लेकिन इससे उपभोक्ता मांग में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि, कई लोग आभूषणों की बजाय ''ठोस सर्राफा'' को तरजीह दे रहे हैं।एमसीएक्स में दिन में सोने की कीमत 1,28,395 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। मुंबई के प्रसिद्ध झावेरी बाजार में उम्मेदलाल तिलोकचंद झावेरी ज्वेलर्स के मालिक वृषांक जैन ने कहा, सोने की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं और लोग इस पर नज़र रख रहे हैं और निवेश के लिए आ रहे हैं। आभूषणों की मांग धीमी हुई है, लेकिन लोग सोने की छड़ें और सिक्के खरीद रहे हैं। इस त्योहारी मौसम और शादी के मौसम से पहले हम सोने और चांदी की छड़ों की काफी मांग देख रहे हैं। उन्होंने पीटीआई-वीडियो को बताया, कई खरीदार अग्रिम बुकिंग या सोने के सिक्के खरीदकर मौजूदा कीमतों पर ही खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और तेज़ी आने की उम्मीद है। जैन ने कहा कि उपभोक्ता अक्सर सोने को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखते हैं और भारत में इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है क्योंकि धनतेरस जैसे त्योहारों और शादियों जैसे अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। झावेरी बाज़ार में आए एक ग्राहक देवरस भाई परमार ने जैन की बात से सहमति जताई। परमार ने कहा, दिवाली के दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है और यह एक निवेश है। आपात स्थिति में हम सोने के बदले नकद प्राप्त कर सकते हैं... मेरे परिवार में हर दिवाली पर सोना खरीदने की परंपरा रही है। भारतीय सर्राफा आभूषण संघ के प्रवक्ता कुमार जैन ने 'ठोस सर्राफा' खरीदने के चलन की पुष्टि की। उन्होंने आगे कहा, शादियों के लिए लोग अपने पुराने सोने को पुनचक्रण करवाने आ रहे हैं और मांग में कोई कमी नहीं आई है।

सोमन्ना ने तिम्माराजनहल्ली-उरुकेरे खंड का निरीक्षण किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तुमकुरु। रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने गुरुवार को तुमकुरु-दावणगेरे नई रेलवे लाइन परियोजना के हिस्से में 13 किलोमीटर के तिम्माराजनहल्ली-उरुकेरे नई लाइन और तुमकुरु-रायदुर्गा नई रेलवे लाइन परियोजना के हिस्से में 12 किलोमीटर के उरुकेरे- तुमकुरु खंड का मोटर ट्रॉली निरीक्षण किया।

मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में, लगभग 11,800 करोड़ की नौ प्रमुख नई रेलवे लाइन परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा निरीक्षण और प्राधिकरण के बाद, तुमकुरु-उरुकेरे-तिम्माराजनहल्ली खंड में ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि वे 17 अक्टूबर को तुमकुरु-रायदुर्गा नई लाइन परियोजना के अंतर्गत आने वाले दोड्डाहल्ली-पावगड़ा-मदकासिरा खंड का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण में तुमकुरु ग्रामीण के विधायक बी. सुरेश गौड़ा, तुमकुरु शहर के विधायक जी.बी. ज्योति गणेश और निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता प्रसाद और बेंगलूरु मंडल के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक www.dakshinbharat.com

हिजाब विवाद :

शिवनकुट्टी ने स्कूल प्रबंधन से सरकार की आलोचना से बचने के लिए कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम। केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने बृहस्पतिवार को हिजाब विवाद के केंद्र में रहे सेंट रीटा पब्लिक स्कूल के प्रबंधन से इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बयानबाजी से बचने को कहा। यह विवाद तब शुरु हुआ जब कोच्चि स्थित चर्च द्वारा संचालित स्कूल ने अपनी 'ड्रेस कोड' नीति का हवाला देते हुए एक छात्रा के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई। इस पर विवाद बढ़ने के बाद स्कूल ने इस सप्ताह की शुरुआत में विद्यार्थियों के लिए दो दिन की छुट्टी घोषित कर दी।

मंत्री ने कहा कि मुद्दा सुलझा लिया गया है और 'ड्रेस कोड' को लेकर सरकार तथा स्कूल प्रबंधन के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रबंधन, अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) और उनके कानूनी सलाहकार ने 15 अक्टूबर को मीडिया में दिए गए बयानों के माध्यम से मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। शिवनकुट्टी ने कहा, ''बुधवार को दिए गए उनके बयानों में कुछ धमकियां थीं। उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग की छवि खराब दिखायी।''

मंत्री ने कहा कि जब भी कोई शिकायत मिलती है तो विभाग द्वारा जांच करना सामान्य बात है। उन्होंने बताया कि इसी प्रक्रिया के तहत शिक्षा उपनिदेशक (डीडीई) ने हिजाब मामले की जांच की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, ''दुर्भाग्यवश, बाद में हमने देखा कि मामले को जानबूझकर भटकाया गया और उसका राजनीतिकरण किया गया। स्कूल प्रबंधन और उनके वकील के संवाददाता सम्मेलन से यह स्पष्ट है कि उनका इरादा सरकार की आलोचना करना था।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि स्कूलों को देश के कानून के अनुसार काम करना चाहिए और अगर किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो शिक्षा विभाग को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। शिवनकुट्टी ने कहा, ''जब स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो वह प्रबंधन की ओर से आना चाहिए, न कि पीटीए अध्यक्ष या वकील की ओर से।'' उन्होंने कहा, ''मुद्दा सुलझ गया है। उसके बाद कोई भी भड़काऊ बयान अस्वीकार्य है। सरकार अपना रुख स्पष्ट कर रही है।'' इससे पहले, सेंट रीटा पब्लिक स्कूल के प्रबंधन ने कहा था कि वह शिक्षा उपनिदेशक (डीडीई) की रिपोर्ट के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, जिसमें संस्थान की ओर से चूक का आरोप लगाया गया है।

केंद्र तमिलनाडु के मछुआरे और कच्चातीवु का मुद्दा श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के समक्ष उठाए : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह 16 से 18 अक्टूबर तक श्रीलंकाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान मछुआरों की सुरक्षा और कच्चातीवु द्वीप की पुन: प्राप्ति से संबंधित मुद्दों को उनके समक्ष उठाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में उन्होंने बताया कि श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या की दिल्ली यात्रा पाक खाड़ी के मछली पकड़ने के पारंपरिक समुद्री क्षेत्र में भारतीय मछुआरों के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों का समाधान करने का एक मूल्यवान अवसर प्रस्तुत करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''श्रीलंकाई नौसेना द्वारा उत्पीड़न, हमलों और गिरफ्तारी की बार-बार होने वाली घटनाओं के कारण तमिलनाडु के मछुआरा समुदायों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।'' उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, ''वर्ष 2021 से अब तक 106 अलग-अलग घटनाओं में 1,482 मछुआरों और 198 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को पकड़ा गया है, जिससे इन समुदायों को संकट और आर्थिक नुकसान हुआ है।'' स्टालिन ने कहा कि उन्होंने इससे पहले 11 मौकों पर प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष यह मामला उठाया था और विदेश मंत्री को 72 बार ज्ञापन दिया था। उनके अनुसार, तमिलनाडु के मछुआरे पारंपरिक रूप से कच्चातीवु द्वीप के आसपास के जलक्षेत्र में मछली पकड़ते रहे हैं, जो ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा था। मुख्यमंत्री ने कहा, ''केंद्र सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को हस्तांतरित कर दिया। परिणामस्वरूप, हमारे मछुआरों की अब अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के क्षेत्र तक पहुंच प्रतिबंधित है और उन्हें घुसपैठ के आरोप में अक्सर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।'' उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कच्चातीवु को पुनः प्राप्त करने तथा पाक खाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु के मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की बहाली के लिए अमरसूर्या के साथ बातचीत शुरु करने का आग्रह किया।

अशोक लेलैंड को तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम से 1,937 बस का ऑर्डर मिला

चेन्नई/नई दिल्ली। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड को तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम से 1,937 बसों का ऑर्डर मिला है। अब तक कंपनी ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को 21,000 बसों की आपूर्ति कर चुकी है। अशोक लेलैंड ने अपने बयान में कहा कि प्रत्येक वाहन को नवीनतम एआईएस 153-मानकों के अनुरूप चेसिस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों का पालन करता है।

अशोक लेलैंड की राष्ट्रीय बिक्री प्रमुख (एमएचसीवी) माधवी देशमुख ने कहा, तमिलनाडु हमेशा से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार रहा है और यह ऑर्डर हमारे ग्राहकों द्वारा अशोक लेलैंड की प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन में रखे गए भरोसे का प्रमाण है।''

तमिलनाडु विधानसभा ने सिद्ध विवि की स्थापना संबंधी विधेयक पर राज्यपाल की राय को खारिज किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर सिद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक पर राज्यपाल आर.एन. रवि की राय को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया और कहा कि केवल विधायकों को संशोधन का प्रस्ताव देने का अधिकार है और कानून बनाना विधानसभा का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रस्तावित तमिलनाडु सिद्ध चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 का उल्लेख करते हुए कहा कि चूंकि यह वित्त विधेयक की श्रेणी में आता है, इसलिए विधानसभा द्वारा इस पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के तहत राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त की जाती है।

उन्होंने कहा कि जनता की राय जानने के बाद, स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए विधेयक के मसौदे को विधि विभाग द्वारा सत्यापित किया गया और स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमण्यम द्वारा इस पर विचार किया गया। बाद में उस मसौदा विधेयक की एक प्रति राज्यपाल रवि को भेजी गई। उन्होंने कहा कि हालांकि, राज्यपाल ने संविधान के तहत निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का पालन किए बिना, मसौदा विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, राज्यपाल ने सदन को भेजे अपने संदेश में यह शर्त रखी कि विधानसभा में विधेयक पेश किए जाने के समय उनके विचारों को सदस्यों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

स्टालिन ने कहा, यह संविधान और हमारी विधानसभा के नियमों के विपरीत है। जब विधानसभा में किसी विधेयक पर बहस होती है, तो केवल जनता द्वारा चुने गए विधायकों को ही संशोधन प्रस्तावित करने, ऐसे संशोधनों को वापस लेने (यदि सरकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण विधायकों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है) या मतदान कराने का अधिकार होता है। राज्यपाल को विधानसभा में पारित होने से पहले किसी विधेयक पर राय व्यक्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए, यह विधानसभा राज्यपाल से प्राप्त संदेश में शामिल विचारों को स्वीकार नहीं कर सकती। स्टालिन ने कहा, ''कानून बनाना इस विधानसभा का विशेषाधिकार है। चूंकि राज्य की स्वायत्तता में विश्वास रखने वाला कोई भी विधायक राज्यपाल के संदेश (मसौदा विधेयक पर अपनी राय तक) को विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज होने की बात स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मैं (मसौदा विधेयक पर) ऐसी राय को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करना चाहता।''

स्टालिन ने राज्यपाल की राय को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तमिलनाडु सिद्ध चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 (16 अक्टूबर, 2025 को सदन में पेश) का उद्देश्य राज्य में सिद्ध, आयुर्वेद, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। विधेयक के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

चेन्नई मंडल ने पटाखों के खतरों को रोकने के लिए दिवाली सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन के सुरक्षा विभाग ने 16 अक्टूबर को चेन्नई सेंट्रल उपनगरीय टर्मिनल (एमएमसी) पर आगामी दिवाली त्योहार से पहले सुरक्षित और दुर्घटना-मुक्त यात्रा पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। चेन्नई मंडल के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रताप सिंह ने इस पहल का नेतृत्व किया और ईएमयू ट्रेनों में यात्रियों को जागरूकता पैम्फलेट वितरित किए, तथा यात्रियों से सुरक्षित और दुर्घटना-मुक्त त्यौहारी यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की।

कार्यक्रम के तहत, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने खोजी कुत्तों की मदद से उपनगरीय टर्मिनल प्लेटफार्मों पर गहन जाँच की। निरीक्षण के दौरान, एक यात्री के पास पटाखे पाए गए और आरपीएफ टीम ने उसे दंडित किया। जागरूकता फैलाने के लिए सार्वजनिक घोषणाएं की गईं तथा उपनगरीय स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को पर्चे वितरित किए गए।

प्रेस और मीडिया को संबोधित करते हुए, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक ने यात्रियों से आग्रह किया कि वे ट्रेनों या रेलवे परिसर में पटाखे या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने से बचें। कार्यक्रम के दौरान, आर. साथियासीलन, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी; मंजूनाथन, स्टेशन निदेशक; सुब्रमण्यन, सुरक्षा परामर्शदाता और अन्य सुरक्षा शाखा कर्मचारी उपस्थित थे।

रेलवे ने यात्रियों से अपील कि है कि रेलगाड़ियों या रेलवे स्टेशन परिसर में पटाखे या कोई अन्य ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री न ले जाएं। ऐसी वस्तुओं को ले जाने से साथी यात्रियों और रेलवे संपत्ति को गंभीर खतरा हो सकता है। रेल में ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना दंडनीय अपराध है। चेन्नई डिवीजन सभी यात्रियों से अपील करता है कि वे सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और सभी के लिए सुरक्षित, संरक्षित और आनंदमय त्यौहारी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के साथ हाथ मिलाएं।

इंडियन बैंक का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 11.5 प्रतिशत बढ़कर 3,018 करोड़ रुपए

चेन्नई/नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 11.53 प्रतिशत बढ़कर 3,018 करोड़ रुपये हो गया।

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में 2,706 करोड़ रुपये का एकल शुद्ध लाभ अर्जित किया था। इंडियन बैंक ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में ब्याज आय बढ़कर 11,964 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 11,125 करोड़ रुपये थी।

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) दूसरी तिमाही में बढ़कर 2.60 प्रतिशत हो गईं, जो सितंबर 2024 में कुल ऋणों का 3.48 प्रतिशत थीं।

केरल में आरएसएस कार्यकर्ता आनंदू अजी की मौत को लेकर विरोध-प्रदर्शन तेज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोट्टायम/भाषा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े 26 वर्षीय आनंदू अजी की मौत को लेकर युवा कांग्रेस और 'डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' (डीवाईएफआई) के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को केरल के कोट्टायम में अलग-अलग विरोध-प्रदर्शन किया और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। कोट्टायम जिले के थंपलक्कड़ निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजी नौ अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम के थम्पनूर स्थित एक लॉज में मृत पाए गए थे। बताया गया कि उनका परिवार लंबे समय से आरएसएस से जुड़ा हुआ था।

डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने पोनकुन्नम में विरोध मार्च निकाला। उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ता बताए जा रहे निधीश मुरलीधरन को अजी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। वामपंथी युवा संगठन ने कोट्टायम में कुछ आरएसएस नेताओं के खिलाफ जांच की मांग भी की। विरोध के बाद, डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने कंजिरापल्ली के पास कप्पड़ स्थित मुरलीधरन की दुकान तक मार्च निकाला। हालांकि, दुकान बंद थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर परिसर के सामने लगे एक साइनबोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया।

अजी ने 15 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसे सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर साझा किया गया था। इस नोट में उन्होंने शुरू में 'एनएम' नाम के एक व्यक्ति का जिक्र करते हुए उस पर बार-बार यौन शोषण का आरोप लगाया। बाद में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें अजी ने निधीश मुरलीधरन के नाम का खुलासा किया और उन्हें पारिवारिक मित्र बताया। अजी ने आरोप लगाया कि छोटी उम्र से ही उनका यौन शोषण किया गया, जिसके कारण उन्हें गंभीर मानसिक तनाव और 'ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर' हो गया। हालांकि, अजी ने यह भी कहा कि उनके पास इन दावों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है।

आरएसएस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अजी की मौत के बाद इंस्टाग्राम और कुछ अन्य सोशल मीडिया मंचों पर सामने आए सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप ''संदिग्ध और बेबुनियाद'' हैं। इस बीच, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंजिरापल्ली स्थित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला और पुलिस पर सही ढंग से जांच न करने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, उन्हें हिरासत में लिया और फिर मौके से हटा दिया।

युवा कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ओजे जनीश ने आरोप लगाया कि अजी के मुरलीधरन का नाम लेने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा, ''अगर इस मामले में माकपा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) और आरएसएस के बीच कोई सांठगांठ हुई है, तो हम राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शन करेंगे।'' केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस मुद्दे पर विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, ''आरएसएस पहले ही जांच की मांग कर चुका है और पुलिस जांच कर रही है। जांचकर्ताओं को अपना काम करने दें।'' अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने वाली थम्पनूर पुलिस ने कहा कि वह जल्द ही मुरलीधरन से पूछताछ करेगी।

अधिकारियों के अनुसार, ''हम साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जल्द ही उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।'' पुलिस ने बताया कि अजी के सुसाइड नोट और वीडियो में दिए गए बयानों के अलावा, उनके परिवार ने अब तक मुरलीधरन के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उसने बताया कि अजी के मेडिकल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। मुरलीधरन की ओर से फिलहाल इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इंडियन ओवरसीज बैंक का जुलाई-सितंबर तिमाही में मुनाफा 58 प्रतिशत बढ़कर 1,226 करोड़ रुपए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) का जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 58 प्रतिशत बढ़कर 1,226 करोड़ रुपये हो गया। गत वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में बैंक को 777 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इंडियन ओवरसीज बैंक ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी ब्याज आय बढ़कर 5,856 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 5,055 करोड़ रुपये थी। जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सुधरकर 1.83 प्रतिशत हो गईं जो 2024 की इसी तिमाही में कुल ऋणों का 2.72 प्रतिशत थीं।

साउथ इंडियन बैंक का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ आठ प्रतिशत बढ़कर 351 करोड़ रुपए हुआ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। साउथ इंडियन बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ आठ प्रतिशत बढ़कर 351 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। केरल स्थित निजी क्षेत्र के बैंक को वित्त वर्ष 2024-25 की सितंबर तिमाही में 325 करोड़ रुपये का एकल शुद्ध लाभ हुआ था।

वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही के दौरान बैंक की ब्याज आय 1,875 करोड़ रुपये पर स्थिर रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 1,878 करोड़ रुपये थी।

तिमाही के दौरान डूबे कर्ज के लिए प्रावधान घटकर 63 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर अवधि में 110 करोड़ रुपये था। बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) दूसरी तिमाही के दौरान घटकर 2.93 प्रतिशत रह गईं, जो सितंबर, 2024 में कुल कर्ज पर 4.40 प्रतिशत थीं।

अग्निवीरों के छठे बैच की पासिंग आउट परेड हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। अग्निवीरों का छठा बैच गुरुवार को गर्व और उत्साह के साथ भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट में शामिल हुआ। 276 अग्निवीरों की परेड के साथ 24 सप्ताह का गहन भर्ती प्रशिक्षण पूरा हो गया। अब इन सैनिकों को विशेष बल इकाइयों में भेजा जाएगा। परेड का निरीक्षण पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट ब्रिगेडियर योगेश शर्मा ने किया। उन्होंने अग्निवीरों को संबोधित किया और 'ईमानदारी, वफ़ादारी, बहादुरी' को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अग्निवीरों की सराहना की और उनके माता-पिता को बधाई दी।

परेड का नेतृत्व अग्निवीर सरत एस नायर ने किया। अग्निवीर ऋषभ कुमार शॉ को सर्वश्रेष्ठ रिक्रूट का गिल मेडल मिला। शारीरिक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रिक्रूट के लिए चीमा मेडल और एंड्यूरेंस में सर्वश्रेष्ठ के लिए रणजीत मेडल अग्निवीर शिववीर ने जीता।

फायरिंग और हथियार प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए घाडगे मेडल अग्निवीर राजकुमार एस ने जीता। अग्निवीर सरत एस नायर को ड्रिल में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर के लिए छेत्री मेडल से सम्मानित किया गया।

कैबिनेट ने 117 किलोमीटर लंबे बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर को मंज़ूरी दे दी है : डीके शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

- परियोजना 2 साल में पूरी होगी
- भूमि मालिकों के लिए मुआवज़े के चार विकल्प
- किसी भी कीमत पर अधिसूचना रद्द नहीं

बेंगलूरु। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को बताया कि कैबिनेट ने 117 किलोमीटर लंबे बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर को मंज़ूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूर्ववर्ती पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का नाम बदलकर बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर कर दिया गया है और इसे मंज़ूरी मिल गई है। सरकार इतनी बड़ी सड़क परियोजना की घोषणा करके इतिहास को फिर से लिख रही है। भूमि मालिकों को मुआवज़े के चार विकल्प दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, यह कॉरिडोर सड़क परियोजना तुमकुरु रोड को येलहंका, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और मैसूरु रोड होते हुए तुमकुरु रोड से जोड़ेगी। इस सड़क का 73 किलोमीटर हिस्सा उत्तरी बेंगलूरु में और बाकी दक्षिणी बेंगलूरु में होगा। उन्होंने आगे कहा, पिछली सरकार ने इस परियोजना को अधिसूचित तो किया था, लेकिन वापस नहीं लिया था। बेंगलूरु को नाइस रोड के विकल्प की ज़रूरत है। हमने हुडको के माध्यम से इस परियोजना के लिए 27,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने का फैसला किया है।

शुरुआती अधिसूचना 100 मीटर चौड़ी सड़क के लिए थी, लेकिन हमने सड़क की चौड़ाई 65 मीटर रखने का फैसला किया है, जो बेंगलूरु-मैसूरु राजमार्ग जितनी चौड़ी है। भविष्य में मेट्रो परियोजना के लिए इसमें 5 मीटर की चौड़ाई का प्रावधान होगा। शेष 35 मीटर ज़मीन किसानों को मुआवज़े के तौर पर वापस कर दी जाएगी।

मुआवज़े के चार विकल्प

ज़मीन मालिकों को मुआवज़े के चार विकल्प दिए जा रहे हैं। बाज़ार मूल्य से दोगुना मुआवज़ा देने का प्रावधान है। अगर कुछ ज़मीन मालिक व्यावसायिक ज़मीन नहीं चाहते, तो हम उन्हें बीडीए लेआउट में 40 प्रतिशत विकास भूमि उपलब्ध कराएँगे।

परियोजना 2 साल में पूरी होगी

यह परियोजना 2 साल में पूरी हो जाएगी। अगर कुछ ज़मीन मालिक ज़मीन देने से इनकार करते हैं, तो हम मुआवज़े की राशि अदालत में ज़मानत के तौर पर जमा करेंगे और परियोजना को आगे बढ़ाएँगे। किसी भी कीमत पर किसी भी ज़मीन को डी-नोटिफाई नहीं किया जाएगा। बेंगलूरु में बढ़ते ट्रैफ़िक की वजह से दम घुट रहा है, इसलिए सरकार ने यह ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है।

यह पूछे जाने पर कि इस परियोजना की लागत कितनी होगी, उन्होंने कहा, परियोजना का मूल अनुमान 27,000 करोड़ रुपये था। अब चूँकि ज़्यादा किसान ज़मीन के मुआवज़े का विकल्प चुन रहे हैं, इसलिए इस परियोजना की लागत 10,000 करोड़ रुपये से कम होने की संभावना है।

यह पूछे जाने पर कि इस परियोजना से ट्रैफ़िक को कैसे मदद मिलेगी, उन्होंने कहा, हमें ट्रैफ़िक में 40 प्रतिशत की कमी की उम्मीद है क्योंकि आने-जाने वाले वाहन शहर से गुज़रने के बजाय इसी सड़क का इस्तेमाल करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि प्रस्तावित टोल कितना होगा, उन्होंने कहा, मैं अभी इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। यह एक तकनीकी पहलू है और हम इसे बाद में साझा करेंगे। कोई भी सड़क बिना टोल के नहीं चल सकती। यह पूछे जाने पर कि क्या किसान मुआवज़े के कई विकल्प चुन सकते हैं, उन्होंने कहा, 20 गुंटा से कम ज़मीन वालों को केवल नकद मुआवज़ा दिया जाएगा। इससे ज़्यादा ज़मीन वालों को चुनने के विकल्प दिए गए हैं।

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान

जयपुर में बनेगा आधुनिक एआई डेटा सेंटर : अश्विनी वैष्णव

मोदी के आने के बाद गुलामी की मानसिकता से बाहर आया भारत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी, जयपुर शहर की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत गुरुवार को अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 54 निराश्रित एवं गरीब घुमंतू परिवारों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहें। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। दो हजार साल भारत आत्मनिर्भर रहा। दो सो से तीन सो साल अंग्रेज आए, लेकिन हमारी गुलामी की मानसिकता 2014 में बाहर आए। जब मोदी पीएम बने। आत्मनिर्भर भारत को नीतियों में परिवर्तन हुए। 2004 में अटल वाजपेई ने यूपीए को सरकार बनी। तब भारत अर्थव्यवस्था में दस वे स्थान पर था। यूपीए 2014 तक सरकार रही। दस वे नंबर पर ही रहे। यूपीए के दस साल भ्रष्टाचार में खराब हो गए।

फिर मजबूत नेतृत्व मोदी का आया, जिसने हमें गुलाम बनाया था उस देश को पछाड़ कर पांचवे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना। यूपीए में रेलवे का बजट 680 करोड़ था राजस्थान का, काम कैसे होता। आज मोदी राजस्था रेलवे को 10 हजार करोड़ दे रहे है। 55 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 11 साल में इतने काम हुए जितने 60 वर्षों में नहीं हुए। 85 स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है। स्टेशन में हमारी संस्कृति का समावेश है। देश में स्टेशन, हाइवे, एयरपोर्ट बन रहे हैं। अभी जापान के रेलवे मिनिस्टर आए, सूरत से मुम्बई रेल में के गया। अंदर बैठते ही पर्दे, टच बटन देखे, कहा कि ऐसा तो हमारी बुलेट ट्रेन में भी नहीं था। पानी का ग्लास रखा, बोतल टेस्ट किया, ड्राइवर के केबिन में भी पानी नहीं हिला। वंदे भारत ट्रेन में पानी तो नहीं हिला, दुनिया को हिला रही है। नमो भारत, अमृत भारत ट्रेन चली। दस साल पहले मोबाइल फोन बाहर से आते थे, अब 90 फीसदी भारत में बन रहे है।

देश में काम आने वाली सब चीजें धीरे धीरे भारत में बनने लगेंगी। 75साल देश आजादी को हुए, किसी ने संकल्प नहीं लिया आत्मनिर्भर भारत बनाने का, मोदी ने लिया। 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट दी। जैसे ही और मजबूती आई जीएसटी में बड़ी छूट दी। जनता को इसके लाभ मिल रहा है। निर्णायक नेतृत्व की तुम्ही ताकत है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 5 हजार नवयुवकों को राजस्थान में इसकी ट्रेनिंग देंगे। आईटी का जमाना है। जयपुर ने भी एक बड़ा हब और डेटा सेंटर बने, इसका प्रयास करेंगे। जल्द जमीन लेकर एआई डेटा सेंटर बनाएंगे।

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि सभी देश के लोगों से अपील करती हु कि स्वदेशी अपनाए, दिवाली पर वहीं वस्तु खरीदे जो देश में बनी हो। बीजेपी जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में जयपुर प्रभारी और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद मंजू शर्मा, मेयर कुसुम यादव, देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना भी मौजूद रहे।

जैसलमेर बस हादसे के बाद बस का ढांचा बनाने वालों के खिलाफ अभियान

जयपुर। जैसलमेर में बस अग्निकांड के बाद राजस्थान परिवहन विभाग ने निर्धारित सुरक्षा और निर्माण मानकों के उल्लंघन की जांच के लिए बस के ढांचा निर्माताओं के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ओ.पी. बुनकर ने कहा कि जैसलमेर बस हादसे के बाद तत्परता और संवेदनशीलता के साथ व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जोधपुर की एक टीम ने अब तक जोधपुर स्थित 'जैनम कोच क्राफ्टर' परिसर में निर्मित 66 बसों को निरीक्षण के लिए जब्त कर लिया है।

जैसलमेर त्रासदी से संबंधित तकनीकी और नियामक खामियों की जांच के लिए बुनकर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है जिसमें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के दो परिवहन अधिकारी और दो इंजीनियर शामिल हैं। यह टीम बुधवार रात जोधपुर पहुंची और घटनास्थल का दौरा करेगी। राज्य सरकार ने घटना का स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) पुणे को भी आमंत्रित किया है। सीआईआरटी टीम के सप्ताहांत में जैसलमेर आने और जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

इस बीच, राज्यव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान जारी है, जिसके तहत 'बस बॉडी कोड' मानकों के उल्लंघन के लिए अब तक 53 बस जब्त की जा चुकी हैं। परिवहन विभाग ने सभी परिवहन यूनियन से अपील की है कि वे अपने वाहनों का परिचालन शुरू करने से पहले सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग करें।

जैसलमेर बस हादसा: मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर बस हादसे में जान गंवाने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके तहत मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर बस हादसे के मृतको के आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है तथा उन्हें पूरी मदद देने और घायलों के हरसंभव उपचार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके तहत मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिन परिवारों में तीन या अधिक लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपये एवं अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

शर्मा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है। मंगलवार को दोपहर बाद जोधपुर जा रही एक निजी बस में जैसलमेर से रवाना होने के बमुश्किल दस मिनट बाद आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई और 19 यात्री जिंदा जल गए और 16 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर रूप से घायलों में से एक ने मंगलवार रात अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। एक अन्य घायल की बुधवार को मौत हो गई।

जैसलमेर बस हादसे में मृतकों की संख्या 21 हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। राजस्थान के जैसलमेर में हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या बुधवार को बढ़कर 21 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झुलसे हुए 14 लोगों का अब भी यहां इलाज चल रहा है जिनमें से चार जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। अधिकारियों के अनुसार हादसे में झुलसे आठ साल के बच्चे की जोधपुर के एमजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया,चार घायलों को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार ने कथित लापरवाही के लिए चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन कार्यालय के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। प्राथमिक जांच के अनुसार यह निजी स्लीपर बस एक अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में पंजीकृत हुई थी और उसमें कई बदलाव किए गए थे। उन्होंने बताया कि यह वातानुकूलित एसी बस थी, लेकिन इसे 'नॉन-एसी' के रूप में पंजीकृत किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) के सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल ने बस का निरीक्षण किया था लेकिन नियमों के विरुद्ध बदलाव (मॉडिफिकेशन) सहित उल्लंघनों को नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने लापरवाही के लिए चुन्नीलाल और चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक बस में कोई आपातकालीन निकास नहीं था। आपात स्थिति में खिड़की के कांच को तोड़ने के लिए कोई हथौड़ा नहीं था और एक संकरा गलियारा था जिसमें यात्री फंस गए थे। जैसे ही तारों में आग लगी, स्वचालित दरवाजा की 'लॉक प्रणाली' सक्रिय हो गयी, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। बस के अंदर कई शव एक दूसरे के ऊपर पड़े मिले।

सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौत

जयपुर। बालोतरा कस्बे के पास सड़क हादसे में एक एसयूवी गाड़ी में सवार चार दोस्तों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह भीषण हादसा एक एसयूवी के ट्रेलर से टकराने के कारण हुआ। हादसे में एसयूवी कार में आग लग गई और उसमें सवार चार युवकों की जलने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा बालोतरा के सिणधरी क्षेत्र के सड़ा गांव के पास मेगा हाईवे पर हुआ।

गुड़ामालानी तहसील के डाबड़ा गांव के पांच युवक बुधवार देर रात सिणधरी में काम के बाद घर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार उनकी एसयूवी की सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। टक्कर के कारण एसयूवी में आग लग गई और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहन सिंह (35), शंभू सिंह (20), पंचा राम (22) और प्रकाश (28) के रूप में हुई है। चालक दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया।

अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोटा। राजस्थान के बारां जिले में अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया और बाद में एक रैली निकाली जिसमें पार्टी की राज्य इकाई के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया। इस सीट के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा को अयोग्य ठहराए जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। कृषि उपज मंडी मैदान में आयोजित रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कई अन्य नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और लोगों से राज्य विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने का आग्रह किया। रैली को संबोधित करते हुए भाया ने कहा कि जिन लोगों ने उन पर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाए और पुलिस में मामले दर्ज कराए, वे अब खुद सलाखों के पीछे हैं। पायलट ने कहा, उपचुनाव का उद्देश्य सरकार बदलना नहीं है, बल्कि यह राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के वादों और प्रतिबद्धताओं को परखने का एक साधन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दो साल पहले झूठे वादों के जरिए राज्य में सत्ता में आई थी। गहलोत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चित्तौड़गढ़ में दिए गए उस वादे को तोड़ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। गहलोत ने दावा किया, मुख्यमंत्री शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है या कमजोर कर दिया है।

विलायती बबूल के राज्यव्यापी उन्मूलन की तैयारी में सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यभर से विलायती बबूल (प्रोसोपिस जुलिफोरा) के संपूर्ण उन्मूलन के लिए राज्य सरकार ने व्यापक कार्ययोजना की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में आज सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी शामिल रहे।

दिलावर ने जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश से विलायती बबूल के प्रभावी और स्थायी उन्मूलन के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा। वन एवं राजस्व विभागों द्वारा एक स्पष्ट एवं पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश के प्रत्येक गांव में अभियान के रूप में विलायती बबूल के उन्मूलन का कार्य निर्बाध रूप से प्रारंभ किया जाएगा।

उन्होंने वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक आदेश शीघ्र जारी किया जाए ताकि इस पौधे की कटाई के लिए बार-बार अनुमति लेने की आवश्यकता समाप्त हो तथा किसी प्रकार की वैधानिक बाधा न उत्पन्न हो। दिलावर ने बताया कि विलायती बबूल एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, जो प्रदेश की ग्रामीण भूमि, चारागाहों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। इसकी गहरी जड़ें (लगभग 30 फीट तक) और अत्यधिक जल सोखने की क्षमता (15 मीटर तक) भूजल स्तर में गिरावट और मृदा की उर्वरता में कमी का कारण बन रही हैं। इसके कारण देशी पौधों की प्रजातियाँ भी नष्ट हो रही हैं।

दिलावर ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से एक व्यवस्थित और सक्रिय अभियान के रूप में विलायती बबूल का उन्मूलन करने की दिशा में कार्य करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कटाई के दौरान अन्य उपयोगी वृक्षों को कोई क्षति न पहुंचे। विलायती बबूल के कोयले के परिवहन में आने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए परिवहन की अनुमति प्रणाली को सरल बनाया जाए। दिलावर ने सुझाव दिया कि इस पौधे के पुनः उगने की प्रवृत्ति को देखते हुए राज्य सरकार को इसके उन्मूलन के लिए तीन से चार वर्ष की दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करनी होगी।

ओटाराम देवासी ने कहा कि यह पौधा हमारे चारागाह, कृषि भूमि, नदियों/नालों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, जिसे जड़ से खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मनरेगा और स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर चरणबद्ध तरीके से इसका उन्मूलन किया जाए और सभी विभागों और आम जनता के सहयोग से हम जल्द ही विलायती बबूल मुक्त राजस्थान का सपना साकार करेंगे।डॉ. जोगा राम, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग सहित वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, जल संसाधन एवं संग्रहण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने सांसद बेनीवाल पर पलटवार किया

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के उस बयान पर बुधवार को पलटवार किया जिसमें जैसलमेर बस हादसे में झुलसे लोगों को हवाई मार्ग से अस्पताल नहीं पहुंचाए जाने पर सवाल उठाया था। बेनीवाल ने सवाल किया था कि राठौड़ की पत्नी को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से लाया जा सकता है तो हादसे के घायलों को क्यों नहीं? राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पत्नी को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से लाए जाने का खर्च पत्नी की कंपनी ने उठाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया। राठौड़ ने बेनीवाल के बयान को 'घटिया' मानसिकता का बताते हुए कहा कि बेनीवाल की संवेदना मर चुकी है।

उन्होंने कहा, जिन लोगों ने कभी बिजली का बिल जमा नहीं करवाया,घर खाली नहीं किया, वही आज हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि एक ओर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा है जिनकी मैं प्रशंसा करूगा जिन्होंने विपक्ष में होने के बावजूद मेरी पत्नी की कुशलक्षेम पूछी। वहीं दूसरी ओर बेनीवाल हैं जो इतनी घटिया मानसिकता के साथ अनर्गल आरोप लगा रहे है।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व सांसद बेनीवाल ने सवाल उठाया कि सैन्य हेलीकॉप्टर उपलब्ध होने के बावजूद गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए हवाई मार्ग से अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया। बेनीवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में सवाल किया, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा पूछना चाहता हूं कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ की धर्मपत्नी को बीमार होने पर जब आप उन्हें पाली से जयपुर हेलीकॉप्टर में ला सकते हैं तो आज जैसलमेर के निकट बस में हुई भीषण आगजनी में गंभीर रूप से झुलसे हुए नागरिकों को 'एयरलिफ्ट' करके जोधपुर क्यों नहीं लेकर आए?

बेनीवाल ने लिखा,जैसलमेर में तो सेना के हेलीकॉप्टर/विमान भी थे, आप केंद्र से एवं सैन्य अधिकारियों से बात करके तत्काल झुलसे हुए नागरिकों को हवाई मार्ग से जोधपुर या जयपुर लाते ताकि उनका समय पर उपचार शुरू होता। राठौड़ ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के भावी प्रत्याशी के बारे में कहा कि उपचुनाव में हम जनसेवक मैदान में उतारेंगे, जो जनता की सेवा सेवक बनकर करेगा। उन्होंने कहा,भाजपा का प्रत्याशी जनता की अपेक्षा को पूर्ण करने वाला और जन भावनाओं के अनुरूप होगा।

हर राज्य में भगोड़ों के लिए विशेष जेल बनें, रेड नोटिस के बाद पासपोर्ट रद्द किए जाएं : अमित शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को हर राज्य में भगोड़ों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक विशेष जेल बनाने का सुझाव दिया और कहा कि इंटरपोल के 'रेड नोटिस' का सामना कर रहे भगोड़ों के पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाए ताकि प्रत्यर्पण के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार के दावों को कमजोर किया जा सके और सीमा पार उनकी बेरोकटोक आवाजाही को रोका जा सके।

विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी सहित कई भगोड़ों ने विदेशी अदालतों में अपने प्रत्यर्पण का विरोध करने के लिए भारतीय जेलों की 'खराब स्थिति' का मुद्दा उठाया है।

सीबीआई द्वारा आयोजित 'भगोड़ों का प्रत्यर्पण – चुनौतियां और रणनीतियां' विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा, जब तक हम विदेशों से भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी संप्रभुता और हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले भगोड़ों के मन में भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति भय पैदा नहीं करते, तब तक हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते।

वित्तीय अपराधों, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य मामलों में वांछित भगोड़ों को वापस लाने के लिए विभिन्न देशों में भारत के 338 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं।

शाह ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी होने पर उनके पासपोर्ट को निगरानी सूची में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मौजूदा तकनीक के साथ ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब रेड नोटिस जारी होता है, तो भगोड़े की अंतरराष्ट्रीय यात्रा को रोकने के लिए पासपोर्ट रद्द कर दिया जाना चाहिए। अगर हम इस प्रावधान को सिस्टम में शामिल कर सकें, तो इससे भगोड़ों को वापस लाने में मदद मिलेगी।

पूरे देश में एसआईआर कराने का मकसद, वोट चोरी करना है : दिग्विजय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बाराबंकी (उप्र)/भाषा। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे भारत में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का उद्देश्य ''वोट चोरी'' को बढ़ावा देना है, और दावा किया कि 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के घटक दल दस्तावेजी सबूतों के साथ इसका कड़ा विरोध करेंगे।

यहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आये सिंह ने संवाददाताओं से कहा, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए निर्वाचन आयोग की मदद से बिहार में एसआईआर की आड़ में 62 लाख वोट कटवाये हैं। भाजपा ऐसा करके लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, आयोग पूरे भारत में एसआईआर लागू करके वोट चोरी करेगा। 'इंडि' गठबंधन के घटक दल पूरे सबूतों के साथ इसका जमकर विरोध करेंगे।

सिंह ने दावा किया कि भाजपा ने बिहार में आयोग की मदद से 62 लाख वोट भले ही कटवाये हों लेकिन इसके बावजूद वहां 'इंडि' गठबंधन की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 'इंडि' गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और वह भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हराएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग नीतीश सरकार से ऊब चुके हैं।

कांग्रेस ने आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग की, गृह मंत्री को लिखा पत्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बलिया (उप्र)/भाषा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर हमेशा से ''देश-विरोधी गतिविधियों'' में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। राय ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह भी आरोप लगाया कि संघ महात्मा गांधी की हत्या और देश को बांटने के लिए जिम्मेदार है।

राय ने कहा, संघ हमेशा से देश-विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे इसी संगठन का हाथ था और इसने देश को बांटने का भी काम किया। यह संगठन गलत कार्यों में शामिल है और उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संघ पर पाबंदी लगाने की मांग की है।

केरल में एक युवक की कथित आत्महत्या के मामले का जिक्र करते हुए राय ने आरोप लगाया, 26 साल के संघ प्रशिक्षित आनंदू नाम के एक युवक ने अपने सुसाइड नोट में संघ के वरिष्ठ नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि संघ के अंदर किस तरह का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न होता है।

बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए राय ने दावा किया कि 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) गठबंधन एकजुट है और बिहार में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और वह सरकार बनाएगा।

राय ने भाजपा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अपने साथियों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमेशा अपने साथी दलों के साथ खेल खेला है। उसने ओडिशा में बीजू जनता दल को खत्म किया, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गलत किया और अब बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही कर रही है। भाजपा की नीति अपने सहयोगियों को एक-एक करके खत्म करने की है।

भाजपा सरकार ने बिजली व्यवस्था को किया बर्बाद : अखिलेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह चौपट करने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि बिजली निगम खुद अपने ही नियमकायदों की धज्जियां उड़ा रहा है।

यादव ने यहां जारी एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा बिजली व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने की है। उन्होंने कहा, आए दिन बिजली कटौती और बिजली दरों में वृद्धि से लोगों का जीना दूभर हो गया है। 'पावर कारपोरेशन' (बिजली निगम) खुद अपने कायदेकानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। उपभोक्ता को 'प्रीपेड' या 'पोस्टपेड' मीटर चुनने का प्रावधान है, लेकिन विभागीय मनमानी की जा रही है। निगम ने नए कनेक्शन के साथ 'प्रीपेड' मीटर लेना अनिवार्य कर दिया है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देकर और घरों पर स्मार्ट मीटर लगाकर लूट रही है। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए विद्युत कनेक्शन की लागत पहले जहां एक हजार रुपए थी, अब बढ़कर छह हजार रुपए कर दी गई है। भाजपा सरकार की शह पर बिजली निगम अपने इकतरफा निर्णय थोपने पर आमादा है।

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया, मुनाफाखोरी, कंपनियों से चंदा वसूली और ठेकों में कमीशनखोरी के चलते महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। भाजपा ने ठेले, पटरी वालों से लेकर छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और कारखानों तक, सभी के बिजली कनेक्शनों में लूट मचा रखी है।

नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर जीत हासिल करेगा राजग : मोहन यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) एक बार फिर जीत हासिल करेगा। उन्होंने पटना जिले के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल तथा कांग्रेस पर भी निशाना भी साधा और कहा कि बिहार की जनता ने जंगलराज देखा है।

सिद्धार्थ सौरभ 2020 में कांग्रेस के टिकट पर विक्रम विधानसभा से चुनाव जीते थे और उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में पिछले दिनों शामिल हुए। भाजपा के टिकट पर बृहस्पतिवार को अपना नामांकन दाखिल किया है।

यादव ने कहा, नीतीश कुमार ने सुशासन के सिद्धांतों से बिहार को विकास की नई गति दी है। बिहार हर काल में अग्रणी रहा है। अवंतिका (उज्जैन) और पाटलिपुत्र का दो हजार साल पुराना रिश्ता है। सम्राट अशोक जब गद्दी संभालने वाले थे, तब वे उज्जैन में थे और यहीं से बिहार लौटे थे।

उनका कहना था, बिहार महात्मा बुद्ध की धरती है। हमारे प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ ने जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। बिहार की जनता ने जंगलराज भी देखा है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के शासन में लाइसेंस, कोटा और परमिट राज चलता था। कांग्रेस ने युवाओं की प्रतिभा का गला घोंटा और बिहार को बर्बादी की ओर धकेल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार से देश में सबसे अधिक आईएएस अधिकारी निकलते हैं, जो राज्य की प्रतिभा का प्रमाण है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए उन्होंने कहा, लोकनायक ने लोकतंत्र की रक्षा की थी। हमारी पार्टी और राजग में लोकतंत्र जीवित है, इसलिए यहां एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार जी का इतिहास भी यही है।

कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा, लाल किताब वालों को बुद्धि का ह्रास हो गया है। वे न तो भाषा का ध्यान रखते हैं और न ही मर्यादा का। बार-बार उच्चतम न्यायालय में माफी मांगते हैं, लेकिन सुधारते नहीं। कांग्रेस आज भी परिवारवाद की गिरफ्त में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आर्थिक तंत्र में बड़ा बदलाव आया है।

यादव ने दावा किया, आज गरीबों को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है और दुनिया में भारत की साख बढ़ी है।

कांग्रेस और सपा के चरित्र में 'राजनीतिक ईमानदारी का अभाव': मायावती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चरित्र में 'राजनीतिक ईमानदारी का अभाव' है और केवल बसपा ही हाशिए पर पड़े समुदायों की भलाई और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए ईमानदारी से समर्पित है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की एक विशेष बैठक को संबोधित करते हुए मायावती ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 'राजनीतिक सत्ता की मास्टर कुंजी' हासिल करना और सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति की अपनी विरासत को जारी रखना है।

बयान के मुताबिक, बसपा नेता ने कांशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नौ अक्टूबर को लखनऊ में विशाल राज्य स्तरीय आयोजन की 'ऐतिहासिक सफलता' के लिए उत्तर प्रदेश के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि को हार्दिक बधाई दी।

इस विशाल आयोजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न ट्रेन, निजी बसों, छोटे वाहनों और यहां तक कि पैदल आए लाखों लोगों की ऐतिहासिक भीड़ ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

मायावती ने कहा, हालांकि, प्रतिद्वंद्वी दलों के नेता, जो आमतौर पर रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं, ने यह आरोप लगाकर तुच्छ राजनीति की कि इस आयोजन के लिए सरकारी बसों का इंतजाम किया गया था, जिससे उनकी हताशा जाहिर होती है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने बसपा की उस लिखित मांग को स्वीकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया जिसमें कहा गया था कि बसपा शासन के दौरान निर्मित और लखनऊ में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित स्मारकों और पार्कों की टिकटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व का उपयोग उनके रखरखाव के लिए किया जाए।

मायावती ने कहा, यह बसपा की राजनीतिक ईमानदारी और सद्भावना को दर्शाता है, ऐसे मूल्य जिनकी समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस जैसी पार्टियां कद्र नहीं कर सकतीं क्योंकि राजनीतिक ईमानदारी उनके चरित्र का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसकी 'जातिवादी मानसिकता' के कारण ही उसने बसपा सरकार के दौरान बनाए गए स्मारकों की उपेक्षा की और बहुजन समुदाय के महान संतों, गुरुओं और समाज सुधारकों के सम्मान में स्थापित कई नए जिलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों के नाम बदल दिए।

सिलीगुड़ी में बनेगा महाकाल मंदिर : ममता बनर्जी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सिलीगुड़ी में एक विशाल महाकाल मंदिर बनेगा, जिसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा।

दार्जिलिंग में संवाददाताओं से बातचीत में ममता ने कहा कि मंदिर का निर्माण सिलीगुड़ी में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर के बगल में किया जाएगा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में भगवान शिव का एक नाम महाकाल है।

दार्जिलिंग में महाकाल मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद ममता ने कहा, सिलीगुड़ी में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर के पास एक बड़ा महाकाल मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाना होगा। ममता को दीघा में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है।

मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल में जनसंपर्क कार्यक्रम पर हैं, जहां तेज बारिश और भूस्खलन में भारी नुकसान हुआ था और इस दौरान 32 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि मंदिर के लिए जमीन राज्य सरकार देगी, जबकि मंदिर निर्माण में कुछ समय लगेगा।

बिहार में 'विकास बनाम बुर्के' की शरारत कर रहे हैं कांग्रेस और राजद : योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दानापुर (बिहार)/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को बिहार में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस तथा उनके अन्य सहयोगी दल मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान करने से संबंधित निर्वाचन आयोग के निर्देशों का विरोध कर विकास बनाम बुर्के'' की नई शरारत कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर 'घुसपैठियों' के जरिये फर्जी मतदान करवाने की मंशा रखने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, बिहार राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के शासन में विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। बिहार की एक विकास को बाधित करने के लिए कांग्रेस, राजद और उनके सहयोगी दलों ने एक नई शरारत शुरू की है। यह विकास बनाम बुर्के की शरारत है।

पटना के बाहरी इलाके दानापुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, क्या फर्जी मतदाताओं को वोट डालने दिया जाना चाहिए? कांग्रेस और राजद यही चाहते हैं, इसलिए बुर्के को लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं। यही कारण है कि वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का भी विरोध करते रहे हैं, क्योंकि वे पुराने बैलेट पेपर के उस दौर को वापस लाना चाहते हैं, जिसमें उनके गुर्गे बूथ लूट सकते थे।

उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद अब सीतामढ़ी का भी कायाकल्प किया जा रहा है। दोनों स्थलों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने पर भी काम चल रहा है।

जीवन के अंत तक ओडिशा की सेवा करता रहूंगा : नवीन पटनायक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह जीवन के अंत तक राज्य और यहां के लोगों की सेवा करते रहेंगे। पटनायक ने अपने 79वें जन्मदिन पर पार्टी की वार्षिक 'जन संपर्क पदयात्रा' में शामिल होते हुए यह बात कही।

लगभग छह महीने तक मुंबई और भुवनेश्वर के अस्पतालों में इलाज के बाद पटनायक की यह पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। ठीक होने के बाद उन्होंने लगभग एक महीने तक दिल्ली में आराम किया और पिछले सप्ताह राज्य लौट आए।

ओडिशा के पांच बार मुख्यमंत्री रहे पटनायक ने एकाम्र-भुवनेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नगर पल्ली में मार्च का नेतृत्व किया और बीजद की जन संपर्क पदयात्रा के तहत कुछ कदम चले। पटनायक ने उपस्थित जनसमूह से कहा, मैं हमेशा आपके (ओडिशा के लोगों) साथ हूं, और रहूंगा। मैं जीवन के अंत तक मां ओडिशा की सेवा करता रहूंगा। 'जय जगन्नाथ' के नारे के साथ अपने संक्षिप्त भाषण की शुरुआत करते हुए पटनायक ने बीजद की वार्षिक यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि बीजद आपकी पार्टी है और ओडिशा के लोगों की पार्टी है।

'उत्कलमणि' गोपबंधु दास की जयंती के अवसर पर नौ अक्टूबर को शुरू हुई जन संपर्क पदयात्रा नौ नवंबर तक जारी रहेगी। एक महीने तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान बीजद भाजपा सरकार की कथित विफलता को उजागर करेगी।

यात्रा में शामिल होने के बाद पटनायक ने खंडगिरी क्षेत्र में 'एसओएस' गांव का दौरा किया और वहां के निवासियों के साथ समय बिताया तथा बच्चों को मिठाइयां बांटीं।

शुभेंदु ने बंगाल चुनाव में देरी होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होने की चेतावनी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल)/भाषा। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से सरकार बदलने की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा।

जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में एक जनसभा के दौरान अधिकारी ने कहा कि अगर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा नहीं हुआ तो चुनाव नहीं होंगे। अधिकारी ने कहा, अगर चार मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की हार होगी और एसआईआर चुनाव से पहले 'सेमीफाइनल' साबित होगा।

अधिकारी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी और भाजपा को मिले वोट के बीच का अंतर केवल 42 लाख है। उन्होंने कहा, मतदाता सूची में अवैध रूप से दर्ज लगभग 2.4 करोड़ नाम हटा दिए जाएंगे।

अधिकारी ने जोर देकर कहा कि अवैध प्रवासियों और अन्य कारणों से पात्र नहीं होने वाले लोगों के नाम एसआईआर के बाद मतदाता सूची में नहीं रहेंगे।

पार्टी के लोकसभा सदस्य खगेन मुर्मू पर हुए हमले के विरोध में भाजपा की रैली का नेतृत्व करने के बाद बैठक में अधिकारी ने कहा, मैं भवानीपुर में ममता (बनर्जी) को हराऊंगा। बनर्जी को 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर अधिकारी ने 1,900 से अधिक मतों से हराया था और इसके बाद बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में जीत हासिल की थी।

विदेशी लीग में खेलने से भारतीय खिलाड़ियों को अच्छा अनुभव मिलेगा : शास्त्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सिडनी/भाषा। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने अधिक से अधिक भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति देने की वकालत करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने से उन्हें अच्छा अनुभव मिलेगा।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अभी अपनी सक्रिय खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता। भारतीय क्रिकेटर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने और बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही विदेश में खेल सकते हैं।

अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हाल ही में बिग बैश लीग (बीबीएल) में शामिल होने वाले पहले शीर्ष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने आगामी सत्र के लिए सिडनी थंडर के साथ अनुबंध किया है।

शास्त्री ने विलो टॉक पॉडकास्ट पर कहा, भारत एक विशाल देश है। वहां हर किसी को खेलने का मौका नहीं मिलता, हर कोई सफल नहीं हो पाता। अगर कोई खिलाड़ी टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सकता, लेवल सी या लेवल डी का अनुबंध नहीं पा सकता, तो उसे बिग बैश लीग में खेलने से क्यों रोका जाए। उन्होंने कहा, इन लीग में खेलने का अनुभव उनके लिए मददगार साबित होगा, जैसे आईपीएल ने कई युवा खिलाड़ियों की मदद की है, क्योंकि वे शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं।

शास्त्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोटी के खिलाड़ियों के साथ खेलने और कोचिंग स्टाफ में शामिल पूर्व क्रिकेटरों से भारत के युवा खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, वे दबाव को झेलना सीखते हैं।

सुविचार

चिकित्सक की सर्वोच्च पुकार, उसकी एकमात्र पुकार, बीमार लोगों को स्वस्थ बनाना है ठीक करना, जैसा कि इसे कहा जाता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

'तेजस्वी' ट्रंप का भारत 'ज्ञान'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के संबंध में ऐसे तथ्य पेश कर रहे हैं, जिनका हकीकत से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति प्रतीत होते हैं, जिनका भारत के बारे में सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा गलत जानकारियों से भरा हुआ है, लेकिन उसे इस तरह बयान करते हैं, गोया इनसे बड़ा कोई विशेषज्ञ नहीं है। ट्रंप की यह टिप्पणी अत्यंत हास्यास्पद है, 'हर साल आपके (भारत) पास एक नया नेता होता है। कुछ तो कुछ महीनों के लिए (सत्ता में) रहते हैं और यह साल दर साल होता रहा है...।' ट्रंप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? नब्बे के दशक में कुछ समस्याएं जरूर आई थीं, लेकिन उसके बाद ऐसा कब हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति को चाहिए कि वे इंटरनेट पर कुछ सर्च ही कर लें। भारत में लोकतंत्र मजबूत है। यहां राजनीतिक स्थिरता है। देश में समय पर चुनाव होते हैं। करोड़ों मतदाता नई सरकार चुनते हैं। वर्ष 2014 से तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले डॉ. मनमोहन सिंह ने एक दशक तक देश का नेतृत्व किया था। हर साल नया प्रधानमंत्री हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जरूर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लिया और अब उसे भारत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मई में यह कहकर खुद के ज्ञान का प्रदर्शन किया था कि 'भारत और पाकिस्तान सदियों से लड़ रहे हैं!' भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, जबकि पाकिस्तान तो वर्ष 1947 में बना था। उससे पहले पाकिस्तान का कहीं नामो-निशान नहीं था, लेकिन ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि मैंने सदियों पुरानी लड़ाई बंद करवाकर शांति की स्थापना में अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। वे गलत जानकारी देकर नोबेल पुरस्कार के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहते थे।

डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा भी सच्चाई से परे है कि 'अगर भारत (रूस से) तेल नहीं खरीदता है तो रूस-यूक्रेन युद्ध बहुत आसानी से बंद हो जाएगा।' रूस के पास हथियारों का बड़ा भंडार है। लड़ाई लंबी खींचना उसके लिए असंभव नहीं होगा। यह न भूलें कि चीन भी रूस से तेल खरीदता है। अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता तो कई देशों में ईंधन का संकट पैदा हो सकता था। याद करें, कभी अपने चुनावी भाषणों में ट्रंप यह युद्ध रुकवाने के लिए कितने बड़े दावे करते थे! अब दावे धराशायी हो गए तो भारत पर झूठे आरोप लगाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप जुलाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' बता चुके हैं, जबकि कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपनी रिपोर्टों में अनुमान लगा चुकी हैं कि भारत सबसे ज्यादा तेजी से उन्नति करने वाले देशों में से एक है। इन दिनों जब दीपावली के लिए खरीदारी हो रही है तो कई बाजारों में पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी का बहुत मजबूती से मुकाबला किया था और बहुत जल्द अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। ट्रंप के बयान सुनकर लगता नहीं कि ये कभी अखबार पढ़ते होंगे। इनके अतिशयोक्तिपूर्ण दावे उन लोगों को जरूर भ्रमित कर सकते हैं, जो पढ़ने-लिखने से कोसों दूर हैं। जो व्यक्ति देश-दुनिया की सामान्य जानकारी भी रखता है, वह ट्रंप के झूठ को आसानी से पकड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कभी 100 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, कभी भारत को टैरिफ किंग बताते हैं, तो कभी भारत-पाक संघर्ष विराम कराने का झूठा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की जितनी किरकिरी ट्रंप ने करवाई है, उतनी शायद ही किसी (पूर्व) राष्ट्रपति ने करवाई होगी। भविष्य में भी इतने 'तेजस्वी' राष्ट्रपति दुर्लभ होंगे।

ट्वीटर टॉक

बालोतरा के सड़ा गांव में ट्रेलर और स्कॉर्पियो के बीच हुई भीषण दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें।

-वसुंधरा राजे

आप सभी को विश्व खाद्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ! आइए, हम सभी मिलकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पोषण स्तर को सुदृढ़ बनाने और भोजन की बर्बादी को रोकने का दृढ़ संकल्प लें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त, पौष्टिक और सुरक्षित आहार उपलब्ध हो सके।

-भजनलाल शर्मा

जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में जैसलमेर बस हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों से मुलाकात की एवं उन्हें हिम्मत बंधाई। यहां मौजूद इन पीड़ित परिजनों ने अपनी व्यथा बताई। पीड़ितों ने उनके सामने आ रही दिक्कतों के बारे में बताया ।

-अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

जीवन का सत्यबोध

एक किसान बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा था। खेती-बाड़ी करता था। बहुत दिनों के बाद उनके घर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम हारू रखा गया। माता-पिता दोनों को उस इकलौते पर अत्यधिक स्नेह था। गांव के सभी लोग किसान का आदर करते थे। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था कि किसी ने आकर बताया 'हारू को हैजा हो गया है।' किसान तुरंत घर लौटा और उसने पूरी लगन से उसका उपचार कराया, परंतु अंततः लड़का चल बसा। सभी लोग शोक में डूब गए, पर किसान शांत रहा। वह सबको समझाने लगा कि शोक करने से कुछ नहीं होता। वह फिर खेत पर काम करने चला गया। लौटकर देखा तो उसकी पत्नी रो रही थी। उसने पति से कहा'तुम बड़े निष्ठुर हो! बेटा चला गया और तुम्हारी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला।' किसान ने शांत स्वर में कारण बताया'कल मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा उसमें मैंने स्वयं को राजा देखा, मेरे आठ पुत्र थे और मैं बहुत सुखी था। तभी मेरी आंख खुल गई। अब सोचता हूं, मैं उन आठ बेटों के लिए रोऊं या इस एक हारू के लिए?' किसान ज्ञानी था, इसलिए वह समझ गया था कि जिस प्रकार स्वप्न की अवस्था मिथ्या होती है, उसी प्रकार जागृति की अवस्था भी अस्थायी है।

सामयिक

संवेदनशीलता से ही रोके जा सकेंगे बाल अपराध

अमित बैजनाथ गर्ग

मोबाइल : 78770 70861

अपनी आन-बान-शान और संस्कृति तथा परंपराओं के लिए अनूठी पहचान रखने वाले राजस्थान में लगभग हर तरह के अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। यह स्थिति चिंताजनक तस्वीर खींच रही है। प्रदेश के अपराध बारबार देश में सुर्खियां बन रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 की रपट जारी हुई है। इसमें प्रदेश में कई तरह के अपराधों में इजाफा हुआ है। चाहे महिलाओं पर अपराध हो या फिर बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार, हर क्षेत्र में राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान, असम और केरल जैसे राज्यों में बाल अपराधों की श्रेणी के मामलों में चिंताजनक उछाल आया है।

आइए, सबसे पहले राजस्थान में बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों की कुछ घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जयपुर में अप्रैल, 2025 में 13 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का मामला उजागर हुआ। इसमें बालिका की पहचान छुपाते हुए पुलिस ने दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। वहीं भीलवाड़ा जिले के एक सरकारी स्कूल में 11 वर्षीय छात्रा स्कूल आने के बाद लापता हो गई और बाद में उसका शव मिला। मामले में रेप व हत्या के आरोप में शिक्षक और प्रिंसिपल पर संदेह था। इधर, जून, 2025 में अलवर जिले में 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण, फिरौती और बाद में हत्या कर दी गई। अभियुक्त परिवार का ही सदस्य था। सितंबर, 2025 में भरतपुर के सरकारी अस्पताल में दवा घोटाले के चलते दो बच्चों की संदिग्ध मौत। इसके बाद सीकर में भी एक बच्चे की मौत हो गई। एक मौत की घटना और घटी।

एनसीआरबी की रिपोर्ट चौंकाने वाले भयावह आंकड़ों की ओर इशारा करती है। राजस्थान में बाल अपराध के मामले में 2018 से 2022 के बीच, जहां राजस्थान में हर साल औसतन 6,200 मामले दर्ज हुए, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 10,500 से अधिक हो गई। इस तरह बाल अपराधों में लगभग 70 फीसदी की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि भारत के औसतन 25 प्रतिशत की दर से कहीं अधिक है। राजस्थान जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक गंभीर संकेत है, लेकिन विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यह केवल अपराध बढ़ने का नहीं, बल्कि रिपोर्टिंग के अधिक सटीक और सक्रिय होने का नतीजा भी हो सकता है। बाल अपराध के मामले में राजस्थान की वृद्धि पुलिस के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है।

इधर, राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में अपराधों को लेकर 202425 के कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं।

पुलिस के अनुसार, जनवरी से जून, 2025 के बीच बाल अपराधों में निरंतर वृद्धि रही है। इनमें पॉक्सो एक्ट के तहत 1,631 मामले दर्ज किए गए। वहीं बाल अपहरण अथवा किडनैपिंग के 500 से अधिक मामले सामने आए। साइबर क्राइम में बच्चों को निशाना बनाने के मामलों में 400 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। केवल 53 मामलों में ही चार्जशीट दाखिल हुई। इनमें 186 केस फर्जी निकले। 700 से अधिक मामलों की जांच अभी लंबित चल रही है। इन आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रदेश में जहां एक ओर बाल अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं पुलिस की कार्यशैली बहुत कमजोर नजर आ रही है। पुलिस को इस दिशा में सोचने और तेजी से कार्य करने की सख्त जरूरत है। अब बात करते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की। रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान, असम और केरल जैसे राज्यों में इस श्रेणी के मामलों में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज हुआ है। 2023 में बच्चों के अपहरण के मामलों का हिस्सा कुल बाल अपराधों में 54 फीसदी से ज्यादा रहा। अक्सर ये मामले पारिवारिक विवाद, नाबालिग लड़कियों को प्रेमप्रसंग के बहाने ले जाना या बाल श्रम से जुड़े रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य में हर दो में से एक मामला बच्चों के अपहरण से जुड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि बाल अपराधों के मामले में राजस्थान सबसे आगे रहा है। यह गंभीर संकेत है, जिसे समय रहते समझने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आगे परिणाम और भी चिंताजनक रहेंगे।

बाल अपराधों को रोकने की दिशा में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य में बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में वृद्धि चिंताजनक है। साल 2018 से 2023 तक बच्चों के साथ होने वाली हिंसा के मामले दोगुने से भी अधिक हो गए हैं। बच्चों के साथ होने वाली हिंसा के बढ़ने का प्रमुख कारण बच्चों का सोशल मीडिया के साथ उनकी पहुंच का बढ़ना है। दूसरा मुख्य साथ परिवारों में बढ़ती आपसी हिंसा और अलग होकर एकल परिवार होना है। असल में यह सवाल नीतिगत विमर्श का केंद्र है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों में दर्ज मामलों की बढ़ोतरी का अर्थ हमेशा अपराधों में बढ़ोतरी नहीं होती। पुलिस रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल में सुधार, पॉक्सो जैसे कानूनों की सख्त लागू व्यवस्था और जागरुकता अभियानों से भी आंकड़े ऊपर जा सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि समाज अब ऐसे मामलों को दबाने के बजाय रिपोर्ट करने की ओर झुक रहा है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

अब बात करते हैं पॉक्सो कानून की। इस कानून ने रिपोर्टिंग की तस्वीर बदल दी है। राजस्थान में यौन अपराधों यानी कि पॉक्सो एक्ट से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मामलों के वर्गीकरण में बड़ा बदलाव हुआ है। 2018 से पहले कई मामले भारतीय दंड संहिता की सामान्य धारा 376 (बलात्कार) के तहत दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब इन्हें सही श्रेणी यानी कि पॉक्सो की धाराओं 4 और 6 में दर्ज किया जा रहा है। इस बदलाव ने न केवल कानूनी स्पष्टता बढ़ाई है, बल्कि बच्चों से जुड़े अपराधों की वास्तविक तस्वीर भी सामने आई है। 2022 में जहां ऐसे मामलों की संख्या लगभग 2,700 थी, वहीं 2023 में यह बढ़कर 3,500 से अधिक हो गई। यह दर लगातार तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं समाधानों की। राजस्थान सरकार ने बाल अपराधों के समाधान के लिए बाल संरक्षण इकाइयों को मजबूत करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाने और साइबर सुरक्षा इकाइयों को संवेदनशील बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। इसके अलावा पुलिस को भी इस दिशा में तेजी से कार्य करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। वहीं सामाजिक और गैर सरकारी संगठन भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरुकता अभियान चला रहे हैं। फिर भी इन प्रयासों को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जरूरत है सोच बदलने और जागरूक होने की। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कानून की अपेक्षा सामाजिक सोच में बदलाव से ही तस्वीर बदल सकती है, जिसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। बाल अपराध संवेदनशील विषय है, इसे गंभीर होकर ही समझा और रोका जा सकता है।

विचार

हिंदी के खिलाफ बिल : तमिलनाडु सरकार को क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन लंबे समय से राज्य की पहचानों और सांस्कृतिक स्वायत्तता का प्रतीक बनकर सामने आया है। हाल के घटनाक्रम में डीएमके नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने राज्य में हिंदी फिल्मों, हिंदी गानों और सार्वजनिक होर्डिंग्स तथा बोर्ड्स पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक नया विधेयक लाने की घोषणा की थी। इस प्रस्तावित बिल ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी बहस और तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी सरकार का तर्क था कि यह कदम तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष और कानूनी विश्लेषकों ने इसे संविधान के विरुद्ध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात बताकर विरोध जताया। बिल के मसौदे में यह स्पष्ट किया गया था कि पूरे तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों, सिनेमाघरों, मीडिया, विज्ञापन होर्डिंग्स, और गानों में हिंदी के प्रयोग पर रोक होगी। डीएमके नेताओं का कहना था कि हिंदी का 'थोपना' तिरस्कारपूर्ण ओर तमिल आत्मसम्मान के विपरीत है। राज्य सरकार ने केंद्र शासन, खासकर भाजपा पर ये आरोप लगाए हैं कि त्रिभाषा फॉर्मूला और नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी को दक्षिण भारत में जबरन लागू किया जा रहा है। इसी साल राज्य बजट के लोगो में भी भारतीय रुपया चिन्ह की जगह तमिल अक्षर रखा गया था, जिसे तमिल पहचान और भाषा सम्मान का प्रतीक बताया गया। हालांकि, सरकार द्वारा घोषणा के तुरंत बाद जबरदस्त राजनीतिक और कानूनी प्रतिक्रिया सामने आई। सरकारी सूत्रों के अनुसार, विधेयक पेश करने से पहले एक आपात कानूनी बैठक हुई, जिसमें तमिलनाडु बार और विभिन्न संवैधानिक विशेषज्ञों के सुझाव लिए गए। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 343-351 (संघ की भाषाएँ) के तहत असंवैधानिक साबित हो सकता है। विपक्षी बीजेपी और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि यह कदम सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है और व्यापार, लोकप्रिय संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक असर डालेगा। भाजपा नेता ने इसे मूर्खतापूर्ण और बेतुका बताया तथा इसे राज्य-स्तरीय भावना भड़काने वाला बताया।

जनता और फिल्मी समुदाय ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्रसार माध्यमों पर इसकी आलोचना की। कई लोगों ने तमिलनाडु की भाषा नीति का समर्थन किया, लेकिन हिंदी के पूर्ण बहिष्कार को अनुपयुक्त और संकीर्ण सोच बताया। ऐसा माहौल बना कि तमिल पहचान की रक्षा और भाषाई बहुलता का संतुलन साधना एक मुश्किल राजनीतिक चुनौती है। साथ ही, यह भी आरोप लगे कि डीएमके सरकार यह विवाद ऐसे समय ला रही है जब प्रशासन पर निवेश और रोजगार के कई अहम मसले लंबित हैं। विरोधियों ने इसे ध्यान भटकाने का हथकंडा करार दिया। इन सारे दबावों के बीच सरकार को अपने फैसले की समीक्षा करनी पड़ी। 15 अक्टूबर को प्रस्तावित विधेयक को विधानसभा में रखने से पहले ही स्थगित कर दिया गया। एक बार फिर, सरकार ने बयान दिया कि वह संविधान की सीमा में रहकर ही कोई फैसला लेगी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यापारिक-अधिकारों का सम्मान करेगी। राज्य के वरिष्ठ नेता ने कहा कि डीएमके हिंदी भाषा या उत्तर भारतीय संस्कृति का विरोध नहीं करता, बल्कि उसका विरोध उस प्रक्रिया से है जिसमें एक भाषा को जबरदस्ती थोपने का प्रयास हो। सामाजिक और कानूनी बहस के बाद प्रदेश सरकार ने बिल को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया।

तमिलनाडु की यह घटना भाषाई-सांस्कृतिक संवेदनशीलता, संविधान की रक्षा, कारोबार के व्यापक हित और जनभावना की जटिलता को फिर सामने लाती है। केंद्र सरकार के साथ राज्य का रिश्ता लंबे समय से भाषाई नीतियों के विवाद की वजह से तनावपूर्ण रहा है। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु ने हिंदी के थोपे जाने का दशकों से विरोध किया है, और यह मुद्दा सिर्फ स्कूलों या कार्यालयों की भाषा तक सीमित नहीं, बल्कि तमिल अस्मिता के रक्षार्थ व्यापक सामाजिक संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। वर्तमान दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय पहचान के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सार्वजनिक दबाव, व्यापारिक हित और कानूनी दायरे की टकराहट ने इस बार भी सरकार को कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों के लिए भाषाई मुद्दा न केवल सत्ता की राजनीति का हथियार बना रहा है बल्कि यह क्षेत्रीय अस्मिता के प्रहरी की भूमिका अपना चुका है। विरोधी गुट सरकार के फैसले को 'राजनीतिक स्टंट' बताते हैं, तो समर्थक इसे तमिल स्वाभिमान की रक्षा के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। सरकारी बयान के अनुसार, भविष्य में भी अगर हिंदी को अनिवार्य रूप से थोपने के प्रयास होंगे तो राज्य कानून के दायरे में रहकर कदम उठाएगा। फिलहाल जनता, व्यापारिक समुदाय, फिल्म उद्योग, और राजनीतिक दल इस विषय पर सतर्क हैं। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी विधेयक का स्थगन संविधान, व्यापार और सामाजिक जटिलताओं को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय है, जो आने वाले समय में राज्य की भाषा नीति और केंद्र-राज्य संबंधों की दिशा को भी प्रभावित करेगा।

नजरिया

मुफ्त अनाज सहायता के चक्रव्यूह में फंसी भारत की गरीबी

बाल मुकुन्द ओझा

मोबाइल : 9414441218

हर साल की भांति आज भी यानि 17 अक्टूबर को हम अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने जा रहे है। इस बीच कई बार गरीब की परिभाषा बदली मगर गरीबी उन्मूलन को पूरी तरह अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। इसके विपरीत भारत ने 80 करोड़ से अधिक की अपनी आबादी को मुफ्त अनाज सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपनी सरकार का मंतव्य जाहिर कर दिया। साथ ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा कर दिया। साल दर साल दी जा रही यह खाद्य सहायता कब तक जारी रहेगी, कोई बताने वाला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने भी गरीबी घटने के भारत के इस दावे को स्वीकार कर लिया। विख्यात कृषि अर्थशास्त्री डॉ. गुलाटी की माने तो, जब देश में अत्यधिक गरीबी सिर्फ 5 प्रतिशत है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन क्यों दिया जा रहा है? क्या वे अपना भोजन खरीदने में सक्षम नहीं हैं। दावों प्रतिदावों के बीच गरीबी के खिलाफ संघर्ष आज भी जारी है। विचारणीय बात तो यह है मुफ्त अनाज का यह मायाजाल कब तक जारी रहेगा और आखिर यह गरीबी कब ख़त्म होगी। पैसा फेंक तमाशा देख के इस चक्रव्यूह से आज़ादी कब मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र की गरीबी के खिलाफ संघर्ष की विभिन्न रिपोर्टों का गहन अधयन्न करें तो पाएंगे आज भी दुनियाभर में लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहे है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र ने अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाने की पहल 22 दिसम्बर 1992 को की थी। यह लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को उजागर करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का एक वैश्विक मंच है। यह दिन गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के महत्व को उजागर करता है।

दुनिया भर में गरीबी की स्थिति आज भी बेहद चिंताजनक है। विश्व बैंक के मुताबिक लगभग 700 मिलियन लोग आज भी अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं। रिपोर्ट से साफ़ होता है, दुनिया की एक बड़ी आबादी आज भी बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच नहीं पाई है। हमारे देश की बात करें तो आजादी के 78 सालों के बाद भारत में गरीब और गरीबी पर लगातार अध्ययन और खुलासा हो रहा है। भारत की गरीबी आज भी आंकड़ों के भ्रम जाल में उलझी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सरकार सफल रही है। वहीं 16 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचाया है और गरीब परिवारों के लिए 5 करोड़ घर बनाए हैं। इसके अलावा 12 करोड़ से अधिक शौचालय उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें इन सुविधाओं की कमी के कारण सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती थी।

भारत सरकार ने हर प्रकार की गरीबी को कम करने के लक्ष्य के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी उल्लेखनीय पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे वंचित रहने में काफी कमी आई है। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक का संचालन करते हुए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है, जो ग्रामीण और शहरी आबादी को खाद्यान्न प्रदान करती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाना, सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मातृ स्वास्थ्य का समाधान करने वाले विभिन्न कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन वितरण, सौभाग्य के माध्यम से बिजली कवरेज में सुधार, और स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे परिवर्तनकारी अभियानों ने सामूहिक रूप से लोगों की रहने की स्थिति और समग्र कल्याण की स्थिति में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन धन योजना और पीएम आवास योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने वित्तीय समावेशन और वंचितों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में आने वाली मूलभूत समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है ताकि देश एक विकसित राष्ट्र यानी विकसित भारत 2047 बनने की ओर अग्रसर हो सके। सरकारी स्तर पर यदि ईमानदारी से प्रयास किये जाये और जन धन का दुरुपयोग नहीं हो तो भारत शीघ्र गरीबी के अभिशाप से मुक्त हो सकता है।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

प्रदर्शन

तिरुवनंतपुरम में महिला मोर्चा की सदस्य सबरीमाला मंदिर में सोने की परत चढ़ाने में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुईं।

रूस को भारत के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रखने का भरोसा : उप प्रधानमंत्री नोवाक

मॉस्को/भाषा। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने बृहस्पतिवार को कहा कि रूस को विश्वास है कि भारत के साथ उसका ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। नोवाक का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने उन्हें रूस से तेल खरीदना बंद करने का आश्वासन दिया है। स्वतंत्र समाचार एजेंसी 'इंटरफैक्स' ने नोवाक के हवाले से कहा, हम अपने मित्रवत साझेदारों के साथ सहयोग जारी रखेंगे। हमारे ऊर्जा संसाधनों की मांग बनी हुई है। यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य और व्यावहारिक है। नोवाक रूस के ऊर्जा क्षेत्र को भी देखते हैं। उन्होंने कहा, ...मुझे विश्वास है कि हमारे साझेदार हमारे साथ काम करना, बातचीत करना और ऊर्जा सहयोग विकसित करना जारी रखेंगे।

नोवाक ने यह टिप्पणी ट्रंप के इस दावे के जवाब में की कि जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत, रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि यद्यपि भारत खरीद में तत्काल कटौती नहीं कर सकेगा लेकिन ऐसा करना जरूर शुरू कर देगा।नोवाक ने कहा, आज हमें मीडिया में केवल यही सुनने को मिल रहा है कि हमारे साझेदार यह घोषणा कर रहे हैं कि कोई भी उन पर हुक्म नहीं चला सकता और वे अपना रास्ता स्वयं चुनेंगे।ट्रंप के तेल व्यापार संबंधी दावों के जवाब में भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह बाजार की स्थितियों को पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा स्रोतों को ''व्यापक कर रहा है और उसमें विविधता'' ला रहा है।

भारत ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी आयात नीतियां पूरी तरह से राष्ट्रीय हित पर आधारित होंगी। पारंपरिक रूप से पश्चिम एशियाई तेल पर निर्भर भारत ने फरवरी, 2022 में रूसी सेना के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस से अपने आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की। पश्चिमी प्रतिबंधों और यूरोपीय मांग में कमी के कारण रूसी तेल भारी छूट पर उपलब्ध हो रहा है। स्वतंत्र समाचार एजेंसी 'इंटरफैक्स' के अनुसार, 2025 के पहले सात महीने में रूसी कच्चे तेल का निर्यात 8.75 करोड़ टन या भारत के कुल आयात का 36.4 प्रतिशत रहा।

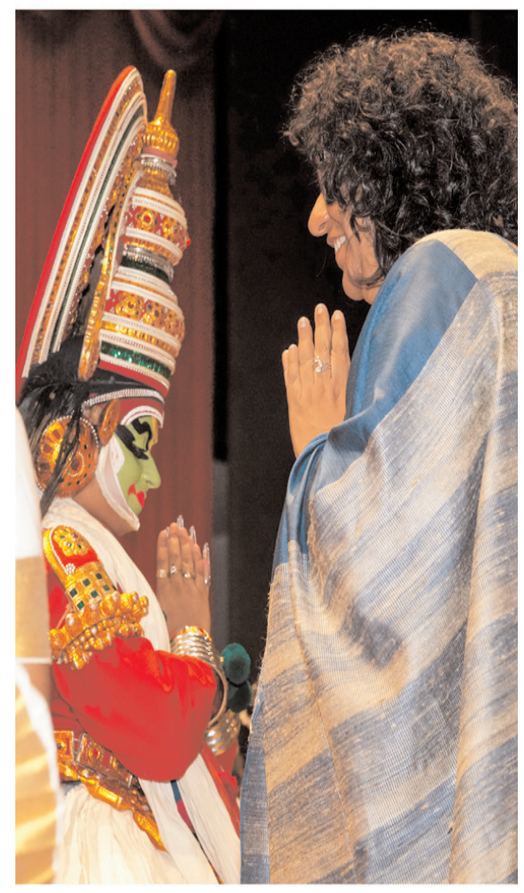

अभिवादन

श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज में अपने दौरे के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली 'कथकली' का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कलाकार से अभिवादन करती हुईं।

जलवायु संकट दुनिया भर में भीषण आग को बढ़ावा दे रहा

मेलबर्न। पृथ्वी के फेफड़े कहलाने वाले अमेज़न के घने जंगलों से उठते धुएं की भयावह तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। स्पेन के अग्निशामक खेत में लगी आग से जूझ रहे हैं। लॉस एंजिलिस में मशहूर हस्तियों के घर धुएं से काले पड़ गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहर धुएं से भरे हैं।

अगर आपको लगता है कि पिछले साल जंगल की आग और उनके प्रभाव अधिक भीषण थे – तो आप सही हैं। हमारी नई रिपोर्ट, जो विभिन्न महाद्वीपों के वैज्ञानिकों के बीच एक सहयोग से तैयार हुई है, दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन ने अप्रत्याशित और विनाशकारी तरीकों से दुनिया में दावानल (जंगल की आग) के स्तर को और बढ़ा दिया है। मानव-जनित जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के कुछ क्षेत्रों में जंगल की आग, जिसे ऑस्ट्रेलिया में बुशफ़ायर कहा जाता है, से जलने वाले क्षेत्र में 30 अप्रत्याशित वृद्धि की है।

हमारे अध्ययन में पिछले वर्ष लगी जंगल की आग के कारणों का पता लगाने और उनकी जांच करने के लिए उपग्रह प्रेक्षणों और उन्नत मॉडलिंग का उपयोग किया गया। शोध दल ने जलवायु और भूमि उपयोग परिवर्तन की भूमिका पर विचार किया और जलवायु तथा चरम घटनाओं के बीच एक स्पष्ट अंतर्संबंध पाया।

क्षेत्रीय विशेषज्ञों ने उन घटनाओं और प्रभावों को दर्ज करने के लिए स्थानीय जानकारी प्रदान की जिन्हें उपग्रहों ने नहीं पकड़ा था। ओशिनिया के लिए, यह भूमिका कंट्री फायर अथॉरिटी की डॉ. सारा हैरिस और मैंने निभाई।

पिछले वर्ष, भारत से भी बड़ा भू-भाग – लगभग 37 लाख वर्ग किलोमीटर – दुनिया भर में जल गया। इस आग से 10 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, और 215 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत के घर और बुनियादी ढांचा खतरे में पड़ गया।

गर्म होती जलवायु का मतलब न केवल अधिक खतरनाक, आग लगने की संभावना वाली परिस्थितियां हैं, बल्कि यह वनस्पति के बढ़ने और सूखने के तरीके को भी प्रभावित करती है, जिससे आग फैलने के लिए ईंधन बनता है।ऑस्ट्रेलिया में, बुशफ़ायर हालांकि पिछले मौसमों, जैसे कि 2019-20 की ब्लैक समर बुशफ़ायर, के समग्र विस्तार या प्रभाव तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आग की 1,000 से ज़्यादा घटनाओं ने लगभग 4,70,000 हेक्टेयर और मध्य ऑस्ट्रेलिया में 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को जला दिया। विक्टोरिया में, ग्रैम्पियंस नेशनल पार्क का दो-तिहाई इलाका जल गया।

हमारे विश्लेषण से पता चला है कि अमेरिका में, जनवरी में लॉस एंजिलिस में लगी जंगल की आग की भयावहता दोगुनी थी और इसने ग्लोबल वार्मिंग के बिना जलने वाले क्षेत्र की तुलना में 25 गुना बड़ा क्षेत्र जला दिया।

पिछले 30 महीनों में लॉस एंजिलिस में असामान्य रूप से नम मौसम ने वनस्पतियों की तेज़ वृद्धि में योगदान दिया और असामान्य रूप से गर्म और शुष्क जनवरी के दौरान जंगल की आग की नींव रखी।

दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे की सीमा पर स्थित पैंटानल-चिकिटानो क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण लगी आग 35 गुना बड़ी थी। रिकॉर्ड तोड़ आग ने अमेज़न और कांगो के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया, जिससे अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड निकली।

अभी देर नहीं हुई है

यह स्पष्ट है कि यदि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही, तो अधिक भीषण गर्मी और सूखे के कारण दुनिया भर में प्रचंड गर्मी की घटनाएं और भी तीव्र हो जाएंगी।

लेकिन अभी भी कार्रवाई करने में देर नहीं हुई है। हमें जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में कटौती, प्रकृति की रक्षा और भूमि की कटाई को कम करने के लिए मज़बूत और तेज़ जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है। हम सूक्ष्म वन प्रबंधन से लेकर घरों की तैयारी और अल्पकालिक व दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन तक, आग के जोखिम से निपटने में बेहतर हो सकते हैं।

आग लगने की घटनाओं में क्षेत्रीय अंतर होते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया भी स्थानीय होनी चाहिए। हमें आग से निपटने में स्थानीय और क्षेत्रीय ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सपना चौधरी ने नसीहत देने वालों को दिया जवाब

मुंबई/एजेन्सी

हरियाणवी डांसर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियत सपना चौधरी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह बना है उनका एक इंस्टाग्राम वीडियो, जिसमें वो पारंपरिक पटियाला सूट पहनकर गलियों में बड़े दिलकश अंदाज में घूमती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनका देसी अंदाज लोगों को खासा पसंद आ रहा है। सपना चौधरी अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने डांस वीडियोज, शायरी और देसी लुक्स साझा करती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए दिल की बात भी साझा की है।

धोखाधड़ी के केस में शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली लॉस एंजेलिस जाने की अनुमति

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) की वजह से शिल्पा को विदेशी यात्रा की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्होंने लॉस एंजेलिस जाने के प्लान को रद्द कर दिया। एक्ट्रेस ने यूट्यूब के एक इवेंट में जाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। उनके वकील ने बताया कि शिल्पा अपनी इस यात्रा की याचिका वापस ले रही हैं और दिसंबर में जब उन्हें फिर से विदेश जाना होगा, तब वे नई याचिका दाखिल करेंगी। धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके कारण दोनों की विदेश यात्रा पर रोक थी। कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बावजूद उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील ने एक नया आरोप भी लगाया है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लगाए गए आरोप 2015 से 2023 के बीच बिजनेसमैन दीपक कोठारी द्वारा कंपनी में 60 करोड़ रुपए निवेश करने से जुड़े हैं। कोठारी का आरोप है कि दोनों ने इन पैसों का इस्तेमाल व्यवसाय में करने की बजाय अपने निजी खर्चों में किया। उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने लोन के रूप में पैसा लिया था, लेकिन बाद में टैक्स की परेशानी के कारण इसे निवेश के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। इस मामले में शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया, जिसे बाद में आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया।

प्रेम, बुद्धिमत्ता और नारी शक्ति का उत्सव है : कावेरी कपूर

मुंबई/एजेन्सी

क्या हर दिन बेटी दिवस नहीं होता? कावेरी के लिए शेखर कपूर का यह दिल को छू लेने वाला नोट – प्रेम, विरासत और कला का प्रतीक है फ़िल्मकार शेखर कपूर, जो जीवन के प्रति अपने काव्यात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी कावेरी कपूर की बचपन की एक प्यारी सी पुरानी तस्वीर के साथ एक बेहद भावनात्मक संदेश साझा किया। जिसमें वह मुक्का मारने वाली नक्काशी वाली एक दीवार के सामने मजाकिया चेहरे के साथ मस्ती से पोज़ दे रही हैं। यह पोस्ट पिता-पुत्री के कोमल, आनंदमय और शाश्वत रिश्ते के सार को खूबसूरती से दर्शाता है। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए इस संदेश की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे सवाल से होती है क्या हर दिन 'बेटी दिवस' नहीं होता? इसके बाद शेखर कपूर ने प्रेम, गर्व और पिता-पुत्री के आध्यात्मिक संबंध पर एक दिल छू लेने वाला मनन साझा किया।

शेखर कपूर अपने शब्दों में बताते हैं कि कैसे कावेरी ने उनके जीवन को एक अर्थ

दिया, और वह डोरी जिसने मुझे जीवन से जोड़ रखा। उनका यह संदेश एक भावनाओं से भरा संदेस प्रतीत होता है, जिसमें पिता अपनी बेटी के प्रति स्नेह और प्रशंसा व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे इस बात पर विचार करते हैं कि कैसे उनकी बेटी कावेरी कपूर, जो एक गायिका-गीतकार, अभिनेत्री और कवियत्री हैं, उनकी दुनिया में अर्थ, आधार और ज्ञान लेकर आई हैं। वो लिखते हैं, तुमने मुझे उससे कहीं ज़्यादा ज्ञान दिया जितना मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता था। सबसे ख़ास बात यह है कि कावेरी में वे जिस जटिल द्वंद्व को देखते हैं, उसे खूबसूरती से व्यक्त करने की उनकी क्षमता, एक युवा मन में बसी प्राचीन आत्मा। वे उसकी रचनात्मकता, करुणा और संवेदनशीलता को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, और बताते हैं कि कैसे उसकी आत्मा कविता, संगीत और जीवों के प्रति सहानुभूति के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करती है। संदेश के अंत में वे लिखते हैं काश मैं तुम्हें तब जानता होता... पर शायद मैं जानता था? इन शब्दों के साथ, शेखर कपूर पाठकों को एक टाइमलेस जुड़ाव का एहसास दिलाते हैं। यह पिता-पुत्री का बंधन अब कला के क्षेत्र में भी एक साथ जुड़ने जा रहा है। दोनों जल्द ही 'मासूम: द नेक्स्ट जेनरेशन' पर काम करने वाले हैं जो शेखर कपूर की प्रतिष्ठित कहानी कहने की परंपरा का अगला अध्याय है। इस प्रोजेक्ट में कावेरी कपूर एक अहम भूमिका निभाएंगी, जो पीढ़ियों के बीच एक रचनात्मक पुल का प्रतीक है। अपनी गहराई, संवेदनशीलता और आत्मीय कलात्मकता के साथ, कावेरी अपने पिता की दृष्टि में एक नया दृष्टिकोण जोड़ती हैं निरंतरता और परिवर्तन, दोनों का सुंदर संगम।

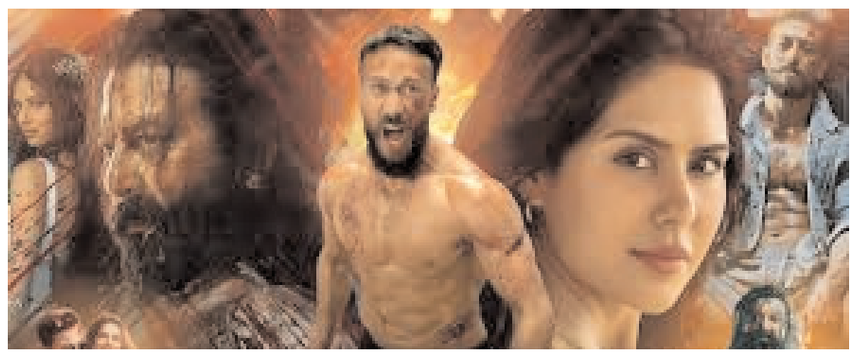

बालिका वधू ने बनाया घर-घर का हिस्सा, उस पर गर्व है : अविका गौर

मुंबई/एजेन्सी

टीवी अभिनेत्री अविका गौर ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में शादी की। वह टीवी सीरियल 'बालिका वधू' के लिए आज भी याद की जाती हैं। इसमें उन्होंने आनंदी का किरदार निभाया था। उनका यह किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया। उन्होंने आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत में बताया कि इस किरदार को जो प्यार लोगों ने दिया, उस पर उन्हें गर्व है। इसकी वजह से ही वह घर-घर फेमस हुईं। जब उनसे पूछा गया कि लोग उन्हें अब भी आनंदी कहकर पुकारते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है? इसका जवाब देते हुए अविका गौर ने कहा, सच कहूं तो, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। अब यह मेरा दूसरा नाम जैसा लगता है। आज ही एयरपोर्ट पर एक

अनजान महिला सामने आईं और मेरे गाल खींचते हुए मुझे आनंदी कहने लगीं। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे यह नाम देना बंद करें क्योंकि यह एक ऐसी पहचान है जो मुझे इस देश के हर घर से जोड़ती है। उस शो और उस किरदार ने मुझे कई परिवारों की बेटी बना दिया। मैं इसे हमेशा संजोकर रखूंगी। जब नेशनल टीवी पर अविका गौर की शादी होने जा रही थी, तब होस्ट सोनाली बेंद्रे ने उनसे एक सवाल पूछा था। सोनाली ने अविका से पूछा था, 'आपकी शादी सच में होने जा रही है? कैसा लग रहा है?' अविका गौर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझसे यह पूछा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी परवाह है और वह यह सब कैमरे या रियलिटी शो के लिए नहीं पूछ रही हैं, बल्कि उनका हर वाक्य दिल से निकल रहा है। सोनाली मैम के साथ वह मेरे लिए बहुत ही खास पल था। उस दौरान मुझे लगा जैसे मुझे देखा, समझा और सहारा दिया जा रहा है। इसके बाद अविका गौर सोनाली बेंद्रे के गले लग गईं। उनको गले लगाने के बाद अविका गौर को लगा कि जैसे कोई फैमिली मेंबर उन्हें गले लगा रहा है। बता दें कि इस शादी में सारी रस्में निभाई गई थीं, शो के कंटेस्टेंट इसमें लड़के और लड़की के रिश्तेदार बनकर शामिल हुए थे।

मां की मेहनत देखकर फिल्मों से दूर रहना चाहती थीं काजोल

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल सिनेमा की उन सितारों में से हैं जिनकी पूरी पीढ़ी फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही है। उनकी मां तनूजा अपने समय की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। पिता शोमू मुखर्जी फिल्म निर्माता थे, जबकि नानी शोभना समर्थ भी जानी-मानी अदाकारा थीं। हालांकि, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में काजोल ने खुलासा किया कि वह कभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं। काजोल ने बताया, जब मैं बड़ी हो रही थी, मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां बहुत संघर्ष करती थीं। वो सुबह 7 बजे से लेकर देर रात तक काम करती थीं, फिर भी उन्हें उतनी फीस नहीं मिलती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इतनी मेहनत कभी नहीं करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि यही वजह थी कि उन्होंने कभी फिल्मों में आने का सपना नहीं देखा।

काजोल ने कहा कि उन्हें फिल्मों की स्क्रिप्ट भले पसंद आ जाए, लेकिन कुछ विषयों से वो हमेशा दूर रहती हैं। उन्होंने साफ कहा, मैं रेप या छेड़छाड़ से जुड़े सीन नहीं करती। मुझे ऐसे विषय पसंद नहीं और मुझे नहीं लगता कि एक अभिनेत्री के तौर पर खुद को साबित करने के लिए ये जरूरी है। काम बात करें तो, काजोल इन दिनों चैट शो 'टू मच' को होस्ट कर रही हैं, जिसमें उनके साथ ट्विंकल खन्ना भी नजर आ रही हैं।

ओटीटी पर दस्तक देगी टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4'

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' ने पिछले महीने 5 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। एक्शन, थ्रिल और खून-खराबे से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। हालांकि जिन्होंने फिल्म थिएटर में मिस कर दी थी, उनके लिए अब खुशखबरी है, 'बागी 4' की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्माताओं ने फिल्म को दिवाली के खास मौके पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि 'बागी 4' के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो ने हासिल किए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार फिल्म 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर रेंट पर उपलब्ध होगी, जबकि 31 अक्टूबर से सभी दर्शक इसे फ्री में देख सकेंगे। 'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू की यह बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म है। फिल्म का निर्देशन ए. हर्ष ने किया है, जबकि इसके निर्माता साजिद नाडियाडवाला हैं।

फिल्म ने भारत में 62.87 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि वैश्विक स्तर पर कुल कलेक्शन 77.67 करोड़ रुपये तक पहुंचा। 'बागी 4' एक्शन सीरीज़ की चौथी किस्त है।

इस फ्रेंचाइज़ी की पिछली तीन फिल्में 2016, 2018 और 2020 में रिलीज हुई थीं, जिनमें टाइगर श्रॉफ की एक्शन और स्टंट परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया था। अब दिवाली पर डिजिटल रिलीज के साथ दर्शकों को घर बैठे धमाकेदार एक्शन देखने का मौका मिलने जा रहा है। 'बागी 4' के ओटीटी डेब्यू से उम्मीद है कि यह फिल्म अपने रोमांचक दृश्यों और टाइगर श्रॉफ के पावरफुल एक्शन की वजह से ऑनलाइन दर्शकों के बीच नई लोकप्रियता हासिल करेगी।

जप अनुष्ठान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई। यहां किलपॉक तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में मुनिश्री मोहजीत कुमारजीके सानिध्य में जप अनुष्ठान सानंद हुआ। इसमें 344 महिलाओं ने भाग लिया एवं 88 पुरूषों ने भी अपनी सहभागिता निभाई। मुनिश्री मोहजीत कुमारजी की प्रबल प्रेरणा, श्रम एवं मार्गदर्शन से जप अनुष्ठान सुचारू रूप से चला। ऑनलाइन के माध्यम से सैकड़ों अन्य ने भी जप अनुष्ठान में भाग लिया। किलपॉक महिला मंडल अध्यक्ष अनिता सुराणा, मंत्री वनीता नाहर आदि उपस्थित थे।

दुनिया से प्रशंसा मत मांगो : डॉ. समकित मुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां पुरुषवाक्कम स्थित एएमकेएम जैन मेमोरियल ट्रस्ट में विराजमान डॉ. समकित मुनिजी म.सा. के सान्निध्य में गुरुवार को उत्तराध्ययन सूत्र आराधना का 16वां दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुनिश्री ने अपने प्रेरणादायक प्रवचन में कहा कि कुछ पराक्रम मंजिल के करीब ले जाते हैं, जबकि कुछ पराक्रम मंजिल से बहुत दूर कर देते हैं। मुनिश्री ने बताया कि समयक्त पराक्रम ही आत्मा को सच्ची मंजिल की ओर ले जाता है। कर्मों को भगाने के लिए नहीं, बल्कि राग-द्वेष को समाप्त करने के लिए पराक्रम करना ही सच्चा सम्यक्त पराक्रम है। उन्होंने कहा कि सम्यक्त पराक्रम की शुरुआत सम्वेग से होती है - यानी यह भावना कि अब बंधनों में नहीं जीना है, अब आत्मा को स्वतंत्रता की ओर ले जाना है।

उन्होंने कहा कि देव, गुरु, धर्म की वंदना करने से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। पच्चखाण लेने से इच्छाओं पर नियंत्रण आता है और क्षमा-याचना करने से मन प्रसन्न होता है तथा सभी प्रकार के तनाव दूर हो जाते हैं। मुनिश्री ने आगे कहा कि आगम और प्रभु की आराधना हमें आत्मदर्शन का अवसर देती है। जो व्यक्ति कलह करता है, वह ज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे-वैसे कलह समाप्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति वह नहीं जो शास्त्र याद रखे, बल्कि वह है जो जीवन में शांति और सौहार्द बनाए रखे। उन्होंने समझाया कि पुण्य का उदय अधिक होने पर व्यक्ति को भूख कम लगती है, और पाप का उदय होने पर अधिक भूख लगती है। रात में भोजन का त्याग करना चाहिए और केवल शरीर की नहीं, बल्कि नाम, पाप, पद और प्रतिष्ठा की भूख को भी नियंत्रित करना चाहिए। केवल दान की भूख, पुण्य की भूख और ज्ञान की भूख रखनी चाहिए। मुनिश्री ने कहा, दुनिया से प्रशंसा मत मांगो। यदि लोग प्रशंसा करें तो वह अलग बात है, लेकिन यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैंने अच्छा किया है तो मुझे प्रशंसा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमने सुख पाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु वास्तविक सुख केवल तपस्या से ही मिलता है। तपस्या करते समय तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए - झूठ नहीं बोलना, लोभ नहीं करना और हिंसा से दूर रहना। कार्यक्रम का संचालन मंत्री विनयचंद पावेचा ने किया।

मिलावटखोर स्वास्थ्य से करते हैं खिलवाड़ : राष्ट्रसंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां के साहुकारपेट स्थित जैन भवन में राष्ट्रसंत श्री कमलमुनिजी कमलेश ने गुरुवार को अपने प्रवचन में कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करके मानवता बीमारियों का घर और आकाल मौत का शिकार बना रहे हैं। मौत के सौदागर, दरिंदे, राक्षस और शैतान से कम नहीं है। 'शुद्ध के लिए युद्ध' विषय पर सेमिनार को संबोधित करते कहा कि असली दिखाकर नकली देना, कम तोलना, मिलावट करके, लाखों जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के समान है। उन्होंने कहा कि यहां तक भगवान के उपयोग में आने वाली वस्तुओं में भी मिलावट करके धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं।

धर्म और परमात्मा को धोखा दे रहे हैं उनसे बड़ा आतंकवादी और कोई नहीं हो सकता। प्रशासन की नाक के नीचे मानो उनकी मिली भगत से सरेआम नकली दूध सिंथेटिक मावा पनीर मिठाइयां की बाढ़ आ गई है। लगता है सरकार नाम के कोई चीज नहीं है लगता है। अधिकारी कुंभकरण की नींद में सोए हुए हैं। ऐसे दुष्कर्म करने वाले को विश्व के किसी धर्म में प्रवेश नहीं है। दुर्भाग्य है धार्मिकता का पाखंड करते हुए काले कारनामे कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज यहां तक की मरने के लिए आदमी जहर लेकर आया। वह भी नकली निकला और वह सवेरे जिंदा उठ गया।

जैन संत ने कहा कि ऐसे मिलावटखोर देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ऐसे आदमखोर खुलेआम घूमते हैं। यह प्रशासन के मुंह पर तमाचा है। कोई भी धर्म इस प्रकार के मिलावट करने की इजाजत नहीं देता है। नैतिकता के खिलाफ है सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक धर्म गुरुओं को मिलकर ऐसे और असामाजिक तत्वों का बहिष्कार करना चाहिए। सरकार कठोर से कठोर दंड दे ताकि कोई दोबारा ऐसा कोई दुष्साहस नहीं कर सके। भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव पर उत्तराध्यन सूत्र का वांचन हो रहा है। सामूहिक तेले तप का कार्यक्रम भी होने जा रहा है। घनश्याम मुनिजी, कौशल मुनिजी सूत्र का वाचन कर रहे हैं। अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच नई दिल्ली में पूरे देश में दिवाली के त्योहार पर धर्म स्थान में शुद्ध सामग्री बनाकर सस्ती रेट में देने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु दिवाकर मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता एडवोकेट सुरेश गोलेछा ने जनता में जागरूकता लाने का आह्वान किया।

सरलता से सिद्धि की प्राप्ति संभव : उपप्रवर्तक नरेशमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय मागडी रोड़ स्थित गुरु ज्येष्ठ पुष्कर दरबार में उपस्थित श्रद्धालुओं को उपप्रवर्तक नरेश मुनिजी ने उत्तराधययन सूत्र का वाचन करते हुए कहा कि धर्म को जानने के साथ उस पर आचरण करना भी जरूरी है। तभी धर्म श्रवण और जानने की सार्थकता सिद्ध होगी। जो भी चरम शरीरी जीव होते हैं वो अपने जीवन में धर्म साधना को प्रमुखता देते हैं। अतः भगवान महावीर की जगत के भव्य जीवों को अपने उपदेशों में कहा है कि धर्म को जानने के साथ उसे आचरण में लाने का भी प्रयास करें। उन्होंने सूत्र के अध्ययनों पर चर्चा करते हुए कहा कि जीवन के साथ, संयम साधना के मार्ग में भी परिषह उपसर्ग आते रहते हैं लेकिन कायर प्राणी उनका सामना नहीं कर पाता और अंत में हार जाता है, वहीं जो शूरवीर आत्मा होती है वो जीवन यात्रा, साधना में आने वाले सभी कष्टों, उपसर्गों, परिषहों को समभाव पूर्वक सहन करते हुए साधना मार्ग में अपने चरण गतिशील रखता है और सभी परिषहों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने मुक्ति के मंजिल का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है।उन्होंने कहा कि धर्म भी शुद्ध हृदय में ठहरता है। कपट के साथ की गई साधना आपको मुक्ति नहीं दिला सकती है। सरलता का मार्ग ही निर्वाण की तरफ जाता है। सरल आत्मा की मुक्ति निश्चित होती है। उन्होंने कहा कि जब तक आपकी पुण्यवानी है तब तक संसार में आपकी चालाकी चल जाती है लेकिन जब पाप का उदय होगा फिर वहां कोई चतुराई नहीं चलेगी। व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल भोगे बिना इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। जो आत्म गुणों में रुचि रखे वो पर्याय धर्म है। उन्होंने कहा कि जो अपने स्वभाव में जीते हैं वो दूसरों के प्रलोभन में नहीं फंसते हैं। उन्होंने धर्म सभा में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों, माता पिता से यह आव्हान किया कि वे अपने बच्चों को दीवाली पर पटाखे नहीं चलाएं और पटाखों, आतिशबाजी का त्याग करने का संकल्प, नियम लेने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें छह काय जीवों को अभयदान देने की हित शिक्षा प्रदान करें। उन्होंने पटाखों के दुष्परिणामों को बताते हुए कहा कि इससे अपार जन धन की हानि के साथ धन का अपव्यय होता है। भगवान महावीर ने अहिंसा को परम धर्म बतलाते हुए जगत के सभी जीवों की रक्षा का संदेश दिया है। भगवान महावीर के उपदेशों, संदेश को मानकर चलने वाला ही उनका सच्चा अनुयायी कहलाने का अधिकारी बन सकता है। प्रारंभ में श्री शालिभद्र मुनि जी ने सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन स्वाध्याय सामूहिक रूप से सस्वर स्वाध्याय पारायण करवाया। उन्होंने शनिवार को साध्वी डॉ दर्शनप्रभाजी के जन्मोत्सव प्रसंग पर आयोजित 'गुरु पुष्कर दर्शन ट्राफी प्रश्न मंच प्रतियोगिता' की विस्तृत जानकारी देते हुए सबसे इसमें भाग लेने की प्रेरणा दी।

दीक्षा के बाद प्रमेय सागर बने स्वस्ति अरिहंतकीर्ति भट्टारक स्वामी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ अरिहंतगिरी (तमिलनाडु) के भट्टारक चिंतामणी स्वस्ति धवलकीर्ति महास्वामी के कर कमलों से दीक्षा की मांगलिक क्रियाएँ संपन्न करायी गई। प्रमेय सागर को नया नाम स्वस्ति अरिहंतकीर्ति भट्टारक स्वामी प्राप्त हुआ।

दक्षिण भारत की भट्टारक परम्परा का 300 वर्षों के बाद उत्तर भारत में हुआ अद्वितीय शुभारम्भ। प्रमेय सागर पिछले तीन वर्षों से अरिहंत गिरी में धवल कीर्ति स्वामी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। प्रमेय सागर ने लगभग सात वर्ष तक श्रवणबेलगोला में पूर्व कर्मयोगी स्वस्ति चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी के सान्निध्य में विभिन्न सिद्धांत ग्रंथों के पठन करने और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। शैक्षणिक नगरी कोटा में आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज ने दीक्षा के संस्कारों से नवीन भट्टारक को संस्कारित किया। गुजरात के भरूच में समवशरण मंदिर का भट्टारक नियुक्त किया और अभिनव अरिहंतकीर्ति स्वामी नाम से सुशोभित किया। इस अवसर पर उन्हें पगड़ी, चाँदी की पिच्छी, कमण्डल, दण्ड और स्वर्ण मुद्रिका पहनाकर सम्पूर्ण विधि विधान किए गए। इस अवसर पर देश के कोने-कोने से श्रद्धालु तथा दक्षिण भारत से श्रवणबेलगोला तथा अन्य भट्टारकगण उपस्थित रहे ।

मैसूरु में जेबीएन मैसूर महाराजा रेफरल ग्रुप की बैठक सम्पन्न

मैसूरु/दक्षिण भारत । जीतो मैसूरु चैप्टर ने जीतो बिज़नेस नेटवर्किंग पहल के तहत बुधवार को जेबीएन मैसूर महाराजा रेफरल ग्रुप की पाक्षिक बैठक आयोजित की। जेबीएन(जैन बिजनेस नेटवर्क) जीतो की पहल है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक विकास को सशक्त बनाना है।

जेबीएन ग्रुप के टीम लीडर और जेबीएन संयोजक महावीर गादिया ने बैठक की अध्यक्षता की। जीतो के अध्यक्ष विनोद बाकलीवाल ने सभा का स्वागत किया।

चंद्रगुप्त कटारिया ने गत दिनों हैदराबाद में संपन्न हुए जीतो कनेक्ट कार्यक्रम की जानकारी दी। बैठक में केकेजी ज़ोन संयोजक चंद्रगुप्त कटारिया, अपेक्स के संयोजक पुनीत श्रीश्रीमाल, जीतो के मुख्य सचिव गौतम सालेचा, प्रेम पालरेचा, गौतम बाघमार, महिला विंग की अध्यक्ष मोना भटेवरा सहित मनीष शाह और अन्य सदस्य उपस्थित थे। अंत में पुनीत जुगराज ने धन्यवाद दिया।

शाकाहार दिवस पर सात्विक आहार पर कार्यक्रम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भारतीय जैन संघटना कोयम्बटूर महिला शाखा द्वारा विश्व शाकाहार दिवस के अवसर पर 'निर्वाण नोश' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य सात्विक भोजन जीवन की आधार शिला है। स्थानीय एस टी एम पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 30 महिलाओं ने भाग लिया। सात्विक आहार की महत्ता को सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में प्रिया बोथरा ने सुन्दर तरीके से स्वादिष्ट जैन फूड बनाने की कला सिखाई। उन्होंने बताया कि किस अहिंसा का पालन करते हुए स्वस्थ जीवन शैली की तरफ बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के साथ की गयी। महिला शाखा की कार्यकर्त्ता बबिता श्रीश्रीमाल द्वारा अतिथियों का परिचय दिया गया। उपाध्यक्ष रेखा रांका ने शुद्ध जैन आहार पर अपने विचार रखे। बीजेस तमिलनाडु के सचिव राजेश पोखरना ने इस कार्यक्रम के महत्व पर अपने विचार रखे। सात्विक भोजन कार्यक्रम का संचालन महिला शाखा की अध्यक्ष सपना लोढा ने किया। सचिव संगीता सुराणा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया।

आज को सुधारो, कल सिद्धशिला तुम्हारा इंतज़ार करेगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

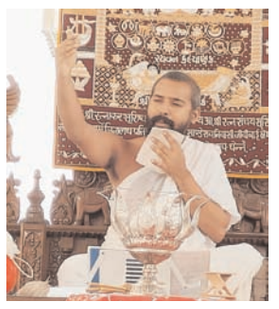

चेन्नई। यहां किलपॉक स्थित एस.सी. शाह भवन में विराजित पंन्यास विमल पुण्यविजयजी म.सा. ने गुरुवार को पुण्यपाल राजा के आठ स्वप्नों की गूढ़ विवेचना करते हुए कहा कि पचक्खाण लेने के लिए उत्साह आवश्यक है और उसे पार करने के लिए सत्व। उन्होंने समझाया कि जब व्यक्ति में उत्साह जागता है, तभी भावना प्रकट होती है, यही भावना साधना का मूल है। एक प्रेरक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह पांचों अंगुलियों में कनिष्ठा अंगुली भी खुल जाए तो मुट्ठी मजबूत नहीं रहती, उसी प्रकार परिवार का छोटा सदस्य भी उसकी स्थिरता के लिए आवश्यक है।

गुरुदेव ने कहा, जहां आपका शरीर विद्यमान है, वहीं मन भी रहे। शरीर का कोई अंग यह दावा नहीं कर सकता कि शरीर उसके कारण चल रहा है। आत्मा ही हंस रूप में जीवन को गतिमान रखती है। उन्होंने श्रोताओं को आगाह किया कि जीवन में नकारात्मक मार्केटिंग से दूर रहें, क्योंकि कर्मसत्ता कब उदय में आए, कहा नहीं जा सकता। जिनशासन में कौए जैसा नहीं, कोयल जैसा बनो। कौआ कांव-कांव किए बिना नहीं रह सकता, जबकि कोयल अपनी मधुरता से सबका मन जीत लेती है। यदि सिद्धशिला पर स्थान पाना है, तो अपने आज को सुधारो, यही वास्तविक साधना है। पंन्यास प्रवर ने समझाया कि गच्छ की व्यवस्था श्रावक-श्राविकाओं के लिए नहीं, बल्कि आराधना के समर्पण हेतु है। यदि इस भव में हम एक-दूसरे से नहीं मिल पाए, तो सिद्धशिला पर भी मिंगल नहीं हो पाएंगे।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी का दोष दिख जाए, तो अधिकृत कदम उठाना चाहिए, अनाधिकृत नहीं। गच्छ केवल एक व्यवस्था है, पक्ष नहीं। संयमकीर्ति विजय म.सा. का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने शिष्य को भी गुरु रूप में मानते थे, ऐसी विभूतियां ही जिनशासन की जीवंतता हैं। गुरुदेव ने कहा, हिंसा में भी अहिंसा और अहिंसा में भी हिंसा का दर्शन, यही जिनशासन का स्यादवाद है। उन्होंने समझाया कि उत्तम संयम का अर्थ है, अपवाद के समय भी निर्दोष या न्यूनतम दोष वाली गोचरी का ही उपयोग। प्रवचन के समापन में उन्होंने कहा, जहां झगड़ा हो रहा है, उसे सुलझाना ही जिनशासन की सबसे बड़ी सेवा है। सुश्रावक शिखर कोचर ने बताया कि आचार्यश्री हीरचंद्रसूरिश्वरजी म.सा. का अखंड सूरि मंत्र पीठिका जाप-अनुष्ठान सुखसाता पूर्वक गतिमान है।

स्तन कैंसर पीड़ितों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। चेन्नई ब्रेस्ट सेंटर ने 'ब्रेस्ट कैंसर से परे : जीवन का पुनर्निर्माण' कार्यक्रम का आयोजन किया, जो तमिलनाडु भर से 100 से अधिक स्तन कैंसर से बचे लोगों का एक विशेष सम्मेलन था, जिनमें से अधिकांश ने पुनर्निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तन पुनर्निर्माण दिवस 2025 पर स्तन कैंसर और पुनर्निर्माण के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

चेन्नई ब्रेस्ट सेंटर के वरिष्ठ सलाहकार, प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जन डॉ. वेंकट रामकृष्णन और वरिष्ठ सलाहकार ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन डॉ. सेल्वी राधाकृष्ण ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें जीवित बचे लोगों ने स्तन कैंसर और पुनर्निर्माण पर वीडियो प्रस्तुतियों के साथ-साथ अपनी व्यक्तिगत यात्रा और अनुभव साझा किए।

स्तन पुनर्निर्माण एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें स्तन उच्छेदन (पूरे स्तन को हटाने) के बाद स्तन के आकार को पुनः स्थापित किया जाता है, जिसमें प्रत्यारोपण या रोगी के पेट, पीठ या जांघों से प्राप्त वसा का उपयोग किया जाता है। विश्व स्तन पुनर्निर्माण दिवस, जिसे इठ- दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि स्वास्थ्य लाभ में पुनर्निर्माण की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध विकल्पों, लाभों और इसके भावनात्मक प्रभाव के बारे में शिक्षित किया जा सके। डॉ. सेल्वी राधाकृष्ण ने कहा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और सटीक इमेजिंग ने पहले पता लगाना संभव बना दिया है, जिससे कई महिलाएं लंबे समय तक जीवित रह पाती हैं और उत्पादक जीवन जी पाती हैं। पश्चिम में, स्तन उच्छेदन की सलाह दी जाने वाली महिलाओं को आमतौर पर तुरंत पुनर्निर्माण की पेशकश की जाती है, लेकिन भारत में, इसे अक्सर छोड़ दिया जाता है। परिणामस्वरूप, कई जीवित बचे लोग विकृति, मनोवैज्ञानिक संकट और आत्मविश्वास की कमी के साथ जीते हैं - जो पुनर्निर्माण को कैंसर देखभाल में शामिल करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

डॉ. वेंकट रामकृष्णन ने कहा, स्तन पुनर्निर्माण तकनीकें काफ़ी उन्नत हो गई हैं। स्तन हटाने के साथ-साथ मरीज़ के अपने ऊतकों, अक्सर पेट की चर्बी का उपयोग करके किया जाने वाला माइक्रोसर्जिकल पुनर्निर्माण, सर्जरी में केवल दो घंटे का समय लेता है और अनुभवी सर्जनों द्वारा किए जाने पर इसकी सफलता दर 99 प्रतिशत से ज़्यादा होती है। यह बेहद सुरक्षित है।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.